राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 14 मार्च 2026 वर्ष-9,अंक-48 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

भारत में बन रहे 6,600 मेगावाट के परमाणु संयंत्र

● वर्ष 2031-32 तक बदल जाएगी देश की ऊर्जा सूरत

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा को बताया कि देश में लगभग 6,600 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के संयंत्र निर्माणाधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि 12,723.50 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं योजनाओं के विभिन्न चरणों में हैं और 2031-32 तक पूरा होने का लक्ष्य है। मनोहर लाल ने लिखित उत्तर में कहा कि 6,600 मेगावाट क्षमता के

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण 2029-30 तक पूरा होने का लक्ष्य है। सात हजार मेगावाट क्षमता के अन्य परमाणु संयंत्र योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। भारत की वर्तमान परमाणु क्षमता 8,780 मेगावाट से अधिक है। 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट-घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली पीएसपी को मंजूरी मिल चुकी है। 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) का निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने संसद को बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) में 52,536.49 मेगावाट की स्थापित उत्पादन क्षमता जोड़ी है। 31 जनवरी तक कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 5,20,511 मेगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का हिस्सा 2,63,189 मेगावाट (50.6 प्रतिशत) है।

बंधक बनाए गए नगा समुदाय के 21 लोग मुक्त

● मणिपुर सरकार और केंद्र के साझा प्रयासों को मिली सफलता

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के उखरुल जिले में बंधक बनाए गए तंगखुल नगा समुदाय के सभी 21 लोगों को रिहा कर दिया गया। मणिपुर के गृह मंत्री गोविनदास कोंथौजम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंधक बनाए गए नागरिकों को बचाने में मदद की। तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नगा जनजाति है। कोंथौजम ने विधानसभा में कहा कि बंधकों को गुरुवार सुबह बातचीत और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद मुक्त किया गया। मंत्री ने कहा कि बुधवार को कुछ हथियारबंद नगा युवकों ने कथित तौर पर थवाई

कुकी गांव में घुसकर किसानों की झोपड़ियों को जला दिया और कुकी समुदाय के दो लोगों का अपहरण कर लिया था। जैसे ही अपहरण की खबर फैली, हथियारबंद कुकी लोगों ने इंफाल-उखरुल रोड पर शांगकाई में 21 तंगखुल नगाओं को ले जा रहे तीन वाहनों को रोक लिया और उन्हें बंधक बना लिया। नागरिकों को बचाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में केंद्रीय बलों को भेजा गया था, लेकिन स्थानीय महिलाओं ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बाद में शाम को सेना ने उस क्षेत्र को घेर लिया जहां 21 तंगखुल नगा बंधक बनाए गए थे।

एलपीजी सिलेंडर के लिए देश भर में मारामारी

● पंजाब में एलपीजी सिलेंडर लेकर भागते दिखे लोग ● 2 हजार का कॉमर्शियल सिलेंडर 4 हजार में बिक रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देशभर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लम्बी लाइनें हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2 हजार का कॉमर्शियल सिलेंडर 4 हजार में बिक रहा है। वहीं पंजाब में लोग सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। केरल में करीब 40 फीसदी रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उधर, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई की बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए अपने साथ मिट्टी के चूल्हे लेकर आए थे।

● **एमपी में ऑनलाइन बुकिंग ठप...वेटिंग 7-8 दिन बढ़ी-** मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग लगभग ठप है। सर्वर डाउन होने से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में लोग सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। गैस एजेंसियों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। इधर गैस की किल्लत के बीच इंडक्शन की कीमतें दोगुनी हो गई हैं।

● **उत्तर प्रदेश में चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियां तक बंद-** यूपी में फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई नहीं हो रही है। इसका असर पॉटरी, चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियों तक पड़ रहा। बुलंदशहर में एशिया के सबसे बड़े पॉटरी उद्योग पर पड़ा है। यहां 300-325 यूनिट में से 95 फीसदी पॉटरी यूनिट बंद हैं। 30 हजार से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। यही हाल फिरोजाबाद में बनने वाली चूड़ियों और आगरा की पेठा फैक्ट्रियों का है।

● **बिहार में एजेंसी के बाहर लंबी लाइन; कोयला-लकड़ी के रेट बढ़े-** बिहार में 4 दिन से कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद है। सप्लाई नहीं होने की वजह से होटल, रेस्टॉरेंट पर काफी असर पड़ रहा है। पटना के बाजारों में लकड़ी और कोयले के भाव भी बढ़ गए हैं। जो लकड़ी एक दिन में 10 किलो ही बिकती थी, अब तीन क्विंटल प्रतिदिन खरीदे जा रहे हैं। दरभंगा में सुबह 6 बजे से ही लंबी लाइन लग गई।

राजस्थान में गैस सप्लाई ठप, सिलेंडर की शवयात्रा निकाली

होटल-रेस्टोरेंट में गैस का स्टॉक खत्म होने से बिजनेस ठप होने लगे हैं। कई जगह ताले भी लटकने लगे हैं। वहीं कोटा समेत कई शहरों में हॉस्टल मेस और ढाबों में मजबूरी में लकड़ी, कोयले और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है। कई शहरों में एजेंसियों पर सुबह 5 बजे से ही लंबी लाइनें लग रही हैं और सिलेंडर न मिलने पर लोगों की पुलिस से झड़प तक हो रही है। इस संकट के बीच सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में सिलेंडर की शवयात्रा निकाली।

तेहरान में अलविदा जुमा पर हुआ जबरदस्त धमाका

● इजरायल के खिलाफ जुटे थे हजारों, मच गई अफरातफरी

तेहरान (एजेंसी)। ईरान की राजधानी तेहरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच धमाका हुआ है। यह ब्लास्ट उस वक्त हुआ, जब तेहरान के फिरदौसी चौक पर हजारों लोग ईरान और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने जुटे थे। आज ईद से पहले का आखिरी जुमा है, जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। इस कारण भी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान जब धमाका हुआ तो दहशत फैल गई और लोग मौके से भागते नजर आए। इस धमाके के पीछे ईरानी एजेंसियों को इजरायल का हाथ होने का शक है। अब तक धमाके की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इजरायल ने हमलों की चेतावनी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह धमाका भी इजरायल ने ही किया है। यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ, जब ईरान में अलविदा जुमा मनाया जा रहा है। ईद से पहले के आखिरी जुमा के दिन खूब भीड़ जुटी थी।

ईरान से युद्ध के बीच रूसी तेल पर नरम है अमेरिका

● भारत के अलावा अन्य देशों को भी दी खरीदारी में ढील

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका का युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। कीमतों को बढ़ता देख अमेरिका ने रूसी तेल के प्रति अपनी नरमी दिखाई है। पहले

अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के उपभोक्ता भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी अनुमति दी थी, कुछ वैसी ही ढील अब अमेरिका ने कई अन्य देशों को भी दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह जानकारी दी है।

कच्चे तेल की खरीद की वजह से नहीं होगा रूस को फायदा

स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस रूसी तेल की खरीद की वजह से रूसी सरकार को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की एनर्जी के लिए नीतियों ने यूएस में तेल और गैस का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचाया है, जिससे मेहनती अमेरिकियों के लिए फ्यूल की कीमतें कम हुई हैं।

ईरान से जंग के बीच क्रैश हुआ अमेरिकी विमान

● 4 लोगों की हो गई मौत, हवा में भर रहा था ईंधन

बगदाद (एजेंसी)। इराक में अमेरिका का विमान केसी-135 हवा में फ्यूलिंग के दौरान क्रैश हो गया है। इस विमान में सवार 6 क्रू सदस्यों में से 4 की मौत हो गई है। सैंटकाम के मुताबिक इस क्रैश में न तो दुश्मन की गोलीबारी की जानकारी सामने आई है और न ही अमेरिकी पक्ष की तरफ से की गई फायरिंग की। ईरान पर मिलकर हमला करने वाले अमेरिका और इजरायल को भी युद्ध में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध में अभी तक आधिकारिक रूप से अमेरिका के चार विमान गिर चुके हैं और एक महंगा एयर डिफेंस सिस्टम थाड का रडार भी नष्ट हो चुका है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईंधन भरने वाले एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 6 क्रू सदस्यों में से चार की मौत हो गई है।

दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है भारत

● मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से क्षेत्र में पैदा हुई गंभीर स्थिति पर बातचीत की। पीएम मोदी ने लिखा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। बढ़ते तनाव, नागरिकों की जानमाल की हानि और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की।

● **ईरान युद्ध के बीच पहली बार बोले मोजतबा खामेनेई-** बता दें कि अपने दिवंगत पिता की जगह संभालने के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने पहला बयान जारी कर गुरुवार को कहा कि ईरान अपने खाड़ी अरब के पड़ोसियों पर हमले जारी रखेगा और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के रणनीतिक लाभ का इस्तेमाल अमेरिका व इजराइल के खिलाफ दबाव के लिये करेगा।

सीईसी को हटाने के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस

● 200 से अधिक विपक्षी सांसदों ने कर दिए हैं साइन

नई दिल्ली (एजेंसी)। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए शुक्रवार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिए। इस नोटिस पर 200 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में सात बिंदु हैं। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सात आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा के 130 सांसदों ने और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।

महिलाओं का करियर खत्म हो जाएगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा

● 'पीरियड्स लीव' की याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की दो टूक

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए देशव्यापी मासिक धर्म अवकाश लागू करने की नीति बनाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस तरह का प्रावधान कानूनन लागू कर दिया गया, तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से कतराएंगी और इससे अनजाने में महिलाओं के प्रति लैंगिक रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए यह स्पष्ट किया कि सरकार और संबंधित अधिकारी इस मामले में सभी हितधारकों से परामर्श करके नीति बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं।

● **महिलाओं का करियर खत्म हो जाएगा-** अदालत ने कहा- स्वैच्छिक रूप से (अपनी मर्जी से) छुट्टी देना बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि यह कानूनन अनिवार्य है, तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। कोई भी उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में नहीं रखेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा। यह जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाए हैं।

अब बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे दूध, होगी कार्रवाई

मिलावट की घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में दूध और डेरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। डेरी सहकारी समितियों के सदस्यों को लाइसेंस नहीं लेना होगा यानी जो किसान या पशुपालक किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति से जुड़े हैं और उन्हें दूध देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य खाद्य आयुक्तों को एडवाइजरी जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एफएसएसएआई ने बताया कि कुछ दूध उत्पादक और दूध विक्रेता खुद को पंजीकृत किए बिना या लाइसेंस लिए बिना कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए राज्य के खाद्य आयुक्तों से कहा गया है कि पंजीकरण-लाइसेंसिंग की जरूरतों का सख्ती से पालन किया जाए।

क्रॉस वोटिंग या फिर 'दक्षिणा' के भरोसे हैं उपेंद्र कुशवाहा

● बिहार में होगा खेला, अब भी तस्वीर नजर आ रही धुंधली

पटना (एजेंसी)। बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा। चूंकि पांच सीटों पर छह उम्मीदवार हैं इसलिए मतदान होगा। मतदान होगा तो एनडीए के पांचवें उम्मीदवार के लिए 3 वोट कम पड़ जाएंगे। एनडीए का यह पांचवां उम्मीदवार तभी जीतेगा जब 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करें या फिर पांच या इससे अधिक विधायक मतदान में गैरहाजिर हो जाएं। छठे उम्मीदवार राजद के अमरेन्द्रधारी सिंह तभी जीत सकते हैं जब एआईएमआईएम के पांच और बसपा के एक विधायक उन्हें वोट दें। इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। इसलिए मतदान के दिन इधर से उधर होने की संभावना है।

● **भोज-भात का दौर और 'दक्षिणा'-** अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में गुरुवार से ही भोज-भात दौर चल रहा है। 14 मार्च को उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर भोजन का प्रबंध है। इसके बाद 15 मार्च को संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के यहां भोज है। डिनर डिप्लोमेसी में बहुत कुछ तय होता है। अगर एनडीए की तरफ से भोजन के साथ-साथ कल्याण करने वाले पुरोहितों को 'उत्तम दक्षिणा' देने की भी प्रबंध हो जाए तो पांचवां प्रत्याशी जरूर 'भवसागर' पार कर जाएगा। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। विधायकी कुर्बान कर भी कल्याण करने वालों की कमी नहीं है। 2010 में राजद और कांग्रेस के विधायक पार्टी लाइन को दरकिनार करते हुए वोटिंग कर चुके हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इच्छा मृत्यु केवल कानून ही नहीं, मानवीय गरिमा का प्रश्न

निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि हरीश राणा के मामले में दिया गया निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि संवैधानिक करुणा का एक उदाहरण है। इसमें न्याय, संवेदना और मानवीय गरिमा तीनों का संतुलित रूप दिखाई देता है। वास्तव में यह निर्णय हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन का सम्मान केवल उसे लंबा खींचने में नहीं, बल्कि उसकी गरिमा को बनाए रखने में है। जब उपचार असंभव हो जाए और चिकित्सा केवल पीड़ा को बढ़ाने का माध्यम बन जाए, तब गरिमापूर्ण विदाई भी मानवीयता का ही विस्तार बन जाती है।

(लेखक- ललित गर्ग)

भारतीय समाज में यह गहरी धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की सेवा तब तक की जाए, जब तक उसके प्राण स्वाभाविक रूप से समाप्त न हो जाएं। जीवन की रक्षा और उसकी देखभाल को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में रोगी की सेवा केवल चिकित्सा का विषय नहीं होती, बल्कि भावनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से भी जुड़ी होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि प्रियजन की मृत्यु के बाद भी उसे लंबे समय तक जीवन लौटने की आशा में संभालकर रखा जाता रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौटने की कोई संभावना न हो और उसका अस्तित्व केवल कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों पर निर्भर रह जाए, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल जैविक अस्तित्व को बनाए रखना ही जीवन की रक्षा है? या फिर जीवन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति देने का अधिकार भी स्वीकार किया जाना चाहिए?

इसी जटिल और संवेदनशील प्रश्न के केंद्र में 11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया वह निर्णय है, जिसमें गाज़ियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई। लगभग तेरह वर्षों से कोमा में जीवन बिताने वाले इस युवक के मामले में अदालत का यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश भर नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन खोजने का एक गंभीर एवं संवेदनशील प्रयास भी है। दरअसल, हरीश राणा का मामला हमें यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि इच्छामृत्यु का प्रश्न केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि एक गहरी मानवीय कहानी भी है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है, जिसका जीवन एक दुर्घटना के बाद अचानक बदल गया और जो तेरह वर्षों तक एक मौन जीवन-मृत्यु संघर्ष में जीता रहा। उस संघर्ष में शब्द नहीं थे, संवाद नहीं था, केवल एक स्थिर और असहाय जैविक अस्तित्व था। ऐसे में परिवार, चिकित्सकों और समाज के सामने यह कठिन दुविधा खड़ी हो जाती है कि जीवन को किस सीमा तक कृत्रिम रूप से बनाए रखा जाए।

इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समय के साथ न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए यह स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार केवल सांस लेने या जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी है। इसी संवैधानिक दृष्टिकोण ने आगे चलकर यह प्रश्न उठाया कि यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, तो क्या उसे गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी नहीं होना चाहिए? भारत में इच्छामृत्यु से जुड़ा न्यायिक विमर्श धीरे-धीरे विकसित हुआ है। वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। यह मामला एक ऐसी नर्स का था, जो दशकों तक कोमा की स्थिति में रही। उस निर्णय ने इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। इसके बाद वर्ष 2018 में कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को संवैधानिक मान्यता देते हुए 'लिविंग विल' की अवधारणा को स्वीकार किया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही यह लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है कि यदि वह असाध्य स्थिति में पहुंच जाए तो उसे कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों पर निर्भर न रखा जाए।

हरीश राणा के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों के बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य शेष नहीं रह गया था। चिकित्सा केवल जैविक अस्तित्व को लंबा खींचने का माध्यम बन गई थी। ऐसे में अदालत की स्वीकृति इस कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा केवल जीने में ही नहीं, बल्कि मृत्यु में भी बनी रहनी चाहिए। फिर भी इच्छामृत्यु का प्रश्न अत्यंत जटिल और विवादास्पद रहा है। दुनिया के अनेक देशों में इस विषय पर गंभीर नैतिक और कानूनी बहस चलती रही है। कई देशों ने इसे सीमित परिस्थितियों में कानूनी मान्यता दी है, जबकि कई अन्य देशों में इसके दुरुपयोग की आशंका के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में भी यह विषय संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यहां पारिवारिक संबंधों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक भावनाओं की भूमिका अत्यंत गहरी है।

इसी संदर्भ में जैन धर्म में प्रचलित संथारा या सल्लेखना की परंपरा भी कई बार चर्चा में आती रही है। जैन दर्शन में इसे मृत्यु का महोत्सव कहा गया है। संथारा का अर्थ है-जीवन के अंतिम चरण में धीरे-धीरे आहार और शरीर की आसक्तियों का त्याग करते हुए शांति एवं समाधिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना। जैन आचार विचार में इसे आत्मसंयम और आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च रूप माना गया है। संथारा और आधुनिक इच्छामृत्यु के बीच अंतर भी है और समानताएं भी। संथारा का आधार आध्यात्मिक साधना और वैराग्य है, जबकि आधुनिक इच्छामृत्यु का आधार चिकित्सा विज्ञान और मानवीय पीड़ा से मुक्ति का विचार है। फिर भी दोनों के केंद्र में एक समान भाव दिखाई देता है-जीवन की अंतिम अवस्था में गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान। हालांकि इस परंपरा को लेकर भी न्यायालयों में बहस होती रही है कि क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता माना जाए या आत्महत्या के रूप में देखा जाए। इस बहस ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन और मृत्यु से जुड़े प्रश्न केवल कानूनी तर्कों से हल नहीं होते, बल्कि उनमें नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम भी शामिल होते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक विनोबा भावे ने इस परंपरा की विशेष सराहना की थी। उन्होंने कई अवसरों पर यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि यदि संभव हो तो वे भी जीवन के अंतिम क्षणों में इसी प्रकार की शांत, संयमित और जागरूक मृत्यु प्राप्त करना चाहेंगे।

इसीलिए हरीश राणा का मामला हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि संविधान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदनशील व्याख्या में निहित है। जब न्यायपालिका जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए मानवीय गरिमा और करुणा को केंद्र में रखती है, तब वह केवल कानून का पालन नहीं करती, बल्कि समाज को अधिक संवेदनशील और मानवीय दिशा भी प्रदान करती है। यह भी सच है कि भारत में इच्छामृत्यु को लेकर अभी तक कोई समग्र और स्पष्ट कानून नहीं है। न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद परिवारों और चिकित्सकों को कई बार जटिल प्रक्रियाओं और कानूनी आशंकाओं का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस विषय पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसा कानून बनाते समय दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, यह कि असाध्य रोगियों को अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति मिल सके। दूसरी, यह कि किसी प्रकार के दबाव, स्वार्थ या आर्थिक कारणों से किसी व्यक्ति को इच्छामृत्यु के लिए विवश न किया जा सके। स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शी चिकित्सा मूल्यांकन और रोगी की स्वायत्त इच्छा का सम्मान इस प्रक्रिया के आवश्यक तत्व होने चाहिए।

निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि हरीश राणा के मामले में दिया गया निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि संवैधानिक करुणा का एक उदाहरण है। इसमें न्याय, संवेदना और मानवीय गरिमा तीनों का संतुलित रूप दिखाई देता है। वास्तव में यह निर्णय हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन का सम्मान केवल उसे लंबा खींचने में नहीं, बल्कि उसकी गरिमा को बनाए रखने में है। जब उपचार असंभव हो जाए और चिकित्सा केवल पीड़ा को बढ़ाने का माध्यम बन जाए, तब गरिमापूर्ण विदाई भी मानवीयता का ही विस्तार बन जाती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारत में इच्छामृत्यु के प्रश्न पर व्यापक सामाजिक संवाद हो और एक ऐसा संवेदनशील तथा संतुलित कानूनी ढांचा तैयार किया जाए, जो व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और गरिमा के साथ मरनेकृदोनों का अधिकार सुनिश्चित कर सके।

संपादकीय

मृत्यु में गरिमा

किसी भी समाज में यह प्रबल धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की तब तक सेवा की जाए, जब तक उसके प्राण कुदरती तौर पर न निकल जाएं। खासकर भारतीय समाज में इस मुद्दे को लेकर गहरी संवेदनशीलता रही है। कई स्थानों पर तो अपने आत्मीय की मृत्यु के बाद भी उसे वर्षों तक जीवन लौटने की आस में घर पर रखा गया। लेकिन जब कोई अपना प्रिय उस स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौट पाना संभव ही न हो, तो बदलते वक्त के साथ कानून के दायरे में उसकी मुक्ति की भी बात होने लगी है। हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट का 13 वर्ष से कोमा में रहने वाले एक युवा के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय, जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर भारत में विकसित होते न्यायशास्त्र में नया मोड़ है। किसी असाध्य स्थिति में कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने वाला यह फैसला, अदालत द्वारा पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पहला व्यावहारिक प्रयोग है। निस्संदेह,यह मामला उन रोगियों के परिवारों के सामने उपस्थित पीड़ादायक दुविधा को ही उजागर करता है, जिनके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती। जो महज चिकित्सकीय मदद से ही जीवित रहते हैं। इस मामले में चिकित्सा बोर्डों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं था। इससे केवल जैविक अस्तित्व को ही लंबा खींच दिया गया। बहरहाल, इस बाबत अदालत की स्वीकृति एक कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा, मृत्यु में भी गरिमा तक विस्तारित होनी चाहिए। निस्संदेह, भारत में इच्छामृत्यु पर कानूनी प्रगति धीमी रही है। इस मामले में पहली बार अरुणा शानबाग मामले में ध्यान दिया गया था। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देने के साथ यह मुद्दा अपने चरम पर पहुंचा। दरअसल, इच्छामृत्यु से जुड़ी दुविधा, इससे जुड़े सिद्धांतों के क्रियान्वयन की अनिश्चितता को लेकर बनी रही है। जिसके चलते परिवारों व डॉक्टरों को जटिल प्रकिया व कानूनी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। निस्संदेह, हालिया फैसले से भी न्यायिक दिशा-निर्देशों मात्र पर निर्भर रहने की सीमाएं उजागर हुई हैं। बल्कि यहां तक कि देश की शीर्ष अदालत ने भी निष्क्रिय इच्छामृत्यु, लिविंग विल और जीवन को लेकर अंतिम निर्णय को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। निस्संदेह, ऐसे कानून में नैतिक संवेदनशीलता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के बीच बेहद संतुलन होना चाहिए। यह प्रक्रिया कमजोर रोगियों को दुर्व्यवहार से बचाते हुए, यह भी सुनिश्चित करे कि परिवार और चिकित्सा पेशेवर कानूनी परिणामों के भय के बिना कार्य कर सकें। इस मामले में स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शी चिकित्सा मूल्यांकन और रोगी की स्वायतता का सम्मान आवश्यक है। अंतत, निष्कर्ष यह भी है कि जब उपचार असंभव हो तो चिकित्सा उपायों से रोगी की पीड़ा को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। निस्संदेह, शीर्ष अदालत की कारगर सलाह के मद्देनजर देश के नीति-नियंताओं को एक मानवीय कानूनी ढांचा तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चहिए। जो टाली न जा सकने वाली विषम स्थिति में व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने व मरने की अनुमति दे सके। निस्संदेह, देश में इस बाबत एक संवेदनशील कानून बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।

तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स का गिरना: क्या अर्थतंत्र में महासंकट के संकेत?

(लेखक- सौरभ वार्ष्णेय)

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब भी ऊर्जा संकट गहराता है, उसका सीधा असर वित्तीय बाजारों और आम लोगों की जेब पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी तथा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक गिरावट की ओर गया है। यह गिरावट केवल बाजार की सामान्य हलचल नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़े संभावित बड़े संकट का संकेत भी हो सकती है। वहीं जब मैं इस लेख को लिख रहा हूं तो सेंसेक्स और निफ्टी काफी हद तक गिर चुका है। ऐसे में सरकार के कहने के बावजूद जनमानस इस युद्ध के बीच ऊर्जा का भंडार भरकर रखना चाहता है, यह युद्ध क्या पटकथा लिखेगा कोई नहीं जानता क्योंकि रुस-युक्रेन युद्ध भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ।

भारत जैसे देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। जब वैश्विक स्तर पर तेल-गैस की कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका असर सीधे महंगाई, उत्पादन लागत और व्यापार संतुलन पर पड़ता है। उद्योगों की लागत बढ़ती है, परिवहन महंगा होता है और अंतत- इसका बोझ आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। निवेशकों को भी यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है।

शेयर बाजार का गिरना इसी चिंता का प्रतिबिंब है। निवेशक भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए बाजार से पैसा निकालने लगते हैं। विदेशी निवेशक भी जोखिम से बचने के लिए उभरते बाजारों से पूंजी निकालते हैं, जिससे बाजार में गिरावट और तेज हो जाती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की गति पर पड़ सकता है।

ऊर्जा संकट का दूसरा पहलू राजकोषीय दबाव भी है। सरकार को महंगाई नियंत्रित करने के लिए करों में कटौती, सब्सिडी या अन्य राहत उपाय देने पड़ सकते हैं। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। साथ ही यदि आयात बिल बढ़ता है तो चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन जाता है।

हालांकि यह भी सच है कि शेयर बाजार हमेशा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति का सटीक दर्पण नहीं होता। कई बार वैश्विक परिस्थितियों, भू-राजनीतिक तनाव या निवेशकों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से भी बाजार अचानक गिर सकता है। इसलिए सेंसेक्स की गिरावट को तुरंत महा संकट मान लेना भी उचित नहीं होगा। लेकिन इसे एक चेतावनी संकेत जरूर माना जाना चाहिए।

ऐसे समय में सरकार और नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की है। देश को तेल-गैस के आयात पर निर्भरता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रणनीतिक भंडार बढ़ाने जैसी नीतियों पर तेजी से काम करना होगा। साथ ही आर्थिक सुधारों और निवेश को बढ़ावा देकर बाजार का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है।

अंतत- कहा जा सकता है कि तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स की गिरावट केवल बाजार की घटना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों की याद दिलाती है। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो यह संकट अवसर में भी बदल सकता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इसके गंभीर आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं।

निवेशक दोहरी दुविधा में

वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के बीच आज निवेशक एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाजार में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय तनाव और महंगाई के दबाव ने निवेशकों को दोहरी दुविधा में डाल दिया है। एक ओर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित निवेश विकल्प भी अपेक्षित रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे माहौल में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि निवेशक अपने धन को कहाँ और कैसे सुरक्षित रखें।

हाल के समय में वैश्विक स्तर पर कई घटनाएँ आर्थिक बाजारों को प्रभावित कर रही हैं। तेल-गैस की कीमतों में अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों में बदलाव का असर भारत सहित दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। जब भी वैश्विक स्तर पर संकट गहराता है, निवेशक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में सुरक्षित निवेश भी बहुत आकर्षक नहीं दिख रहा।

दूसरी ओर घरेलू स्तर पर भी निवेशकों के सामने कई सवाल खड़े हैं। महंगाई की दर में उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों की अनिश्चितता और कंपनियों के भविष्य को लेकर आशंकाएँ निवेशकों को निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर रही हैं। शेयर बाजार में निवेश करने पर जोखिम अधिक है, जबकि बैंक जमा या अन्य सुरक्षित विकल्पों में रिटर्न सीमित है। यही कारण है कि निवेशक समझ नहीं पा रहे कि जोखिम उठाकर बाजार में बने रहें या सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाएँ।

निवेशकों की यह दुविधा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। बाजार की अस्थिरता के कारण कई छोटे निवेशक घबराकर अपने निवेश को निकाल लेते हैं, जिससे बाजार में और अधिक गिरावट देखने को मिलती है। वहीं कुछ अनुभवी निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं और गिरते बाजार में निवेश बढ़ाते हैं।

ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को घबराहट में निर्णय लेने के बजाय अपने निवेश को विविध क्षेत्रों में बांटना चाहिए और लंबी अवधि की रणनीति अपनानी चाहिए। इससे जोखिम कम किया जा सकता है और बाजार की अस्थिरता का प्रभाव भी सीमित किया जा सकता है।

सरकार और नियामक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। पारदर्शी नीतियाँ, निवेश के अनुकूल वातावरण और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया जा सकता है।

यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय निवेशकों के लिए परीक्षा का दौर है। दोहरी दुविधा के बीच सही निर्णय वही होगा जो धैर्य, समझ और दीर्घकालिक सोच पर आधारित हो। अगर निवेशक संतुलित रणनीति अपनाते हैं, तो अस्थिर बाजार भी भविष्य के अवसरों में बदल सकता है।

इच्छा का लक्ष्य है खुशी

बुरी आदत को छोड़ने की असमर्थता तुम्हें तकलीफ देती है। जब तुम बहुत पीड़ित होते हो, वह व्यथा तुम्हें उस आदत से छुटकारा दिलाती है। जब तुम अपनी कमियों से व्यथा महसूस करते हो, तब तुम साधक हो। पीड़ा तुम्हें आसक्ति से दूर करती है। यदि अपने दुर्गुणों को हटा नहीं सकते, तो उन्हें विस्तृत कर दो। चिन्ता, अभिमान, प्रोध, कामना, दुख सबको एक और बड़ा आयाम दे दो, एक दूसरी दिशा। छोटे-छोटे विषयों पर नाराज होने का क्या तुक है? नाराज होना है तो अनन्तता के प्रति, ब्रह्म के प्रति हो। यदि तुम अपने अहंकार को नहीं खत्म कर सकते तो अहंकार करो कि ईश्वर तुम्हारे हैं। यदि आसक्ति तुम पर छाई है, तो सत्य के प्रति आसक्त हो जाओ। यदि ईर्श्या तुम्हें सताती है, तो सेवा के लिए ईर्श्या करो। द्वेष के प्रति द्वेष रखो; गुरु से राग करो। दिव्यता के प्रति मदहोश हो जाओ।

इन्द्रिय सुखों की इच्छाएं विद्युत की तरह हैं; जैसे- जैसे वे विषय विस्तुओं की ओर बढ़ती है, निष्प्रभावी हो जाती हैं। अपनी कुशलता से यदि तुम इच्छाओं को अपने भीतर मोड़ सको- अपने अस्तित्व के केन्द्र की ओर- तो तुम्हें मिलेगा एक और आयाम- चिरन्तन सुख, रोमांच, परमानन्द और शात प्रेम। वासना, लोभ और ईर्ष्या इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि ये केवल ऊर्जा हैं और तुम ही इनके स्रेत हो- वह विशुद्ध ऊर्जा। निष्ठा और भक्ति तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखती हैं, तुम्हें उन्नत करती हैं।

जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम स्वयं ही सुख की विद्युत धारा हो, तुम्हारी लालसाएं घटने लगती हैं और प्रशांति आती है। मृत्यु निश्चित है - यह याद रखने से तुम वर्तमान क्षण में सजीव रहते हो, राग और द्वेष से मुक्त। इच्छा खुशी को खत्म करती है, लेकिन सभी इच्छाओं का लक्ष्य है खुशी। जब भी जीवन से खुशी गायब होने लगे, भीतर गहराई में झांककर देखो- तुम पाओगे यह इच्छा के कारण हो रहा है। लेकिन हमारी इच्छा ही केवल खुशी है। कोई जीव आज तक पैदा नहीं हुआ जिसे दुःख की चाह हो- न ऐसा पहले कभी हुआ है, न भविष्य में होगा। जब तुम्हारा छोटा मन इधर-उधर, जब जगह भागते-भागते थक जाता है, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, मेरी इच्छाओं ने मेरी खुशी छीन ली है।

विचार मंथन

गैस संकटः सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत?

(लेखक- सनत जैन)

देश के कई हिस्सों में रसोई गैस को लेकर जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, उसने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के पास ना तो रसोई गैस है ना केरोसिन तेल है और ना ही लकड़ी उपलब्ध हो रही है। कई स्थानों पर तो बिजली सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में घर में खाना बनाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। एक ओर सरकार दावा कर रही है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। देश के सैकड़ो स्थान से इस बात के वीडियो और फोटो समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में प्रदर्शित हो रहे हैं। कई स्थानों पर डीलर खुले तौर पर कह रहे हैं, उनके पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है। पिछले कई दिनों से गैस की बुकिंग और सप्लाई बंद है। यह विरोधाभास केवल प्रशासनिक, नीतिगत और व्यवस्था की समस्या नहीं है वरन उन करोड़ों लोगों की समस्या है जिनके घर पर ना तो चाय बन पा रही है ना खाना बन पा रहा है। जो सरकार के दावों की हकीकत को उजागर कर रहा है। भारत में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों—इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा निजी गैस कंपनियां भी गैस सप्लाई करती हैं लेकिन सभी कंपनियों की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार का तर्क है, इन कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार है। वितरण प्रणाली सामान्य रूप से चल रही है, पर वास्तविकता में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे है। 1800 से 2000 रुपए में एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर कालाबाजारी से मिल रहा है। वही कमर्शियल गैस सिलेंडर 4000 रुपये तक में बिक रहा है। सरकार इसे वितरण तंत्र की गंभीर खामी बताकर पल्ला झाड़ रही है। जमीनी स्तर पर डीलरों का कहना है, उन्हें कंपनियों से समय पर पर्याप्त संख्या में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पोर्टल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। गैस डीलर भी जिस माध्यम से बुकिंग करते हैं उसका भी पोर्टल बार-बार या तो धीमा हो जाता है या बंद हो जाता है। जिसके कारण वह उपभोक्ताओं की मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को कई दिनों तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। जिसके कारण करोड़ों घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है।

इससे सवाल उठता है, यदि उत्पादन और भंडारण पर्याप्त है, तो फिर गैस की आपूर्ति में बाधा क्यों है? इस समस्या से आम आदमी से लेकर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों और शादी ब्याह के आयोजनों में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। गैस के कारण मात्र असुविधा नहीं वरन गैस लूटने तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। रसोई गैस आम परिवारों की बुनियादी आवश्यकता है। इसका कोई विकल्प भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों के करोड़ों परिवार एलपीजी गैस पर निर्भर हैं। ऐसे में गैस की आपूर्ति बाधित होने पर इसका सीधा असर करोड़ों लोगों के जीवनयापन और छोटे व्यवसायों पर पड़ा है। सरकार केवल बयान देने तक सीमित न रहे। सरकार और कार्यपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह गैस की आपूर्ति प्रणाली की वास्तविक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास करे। गैस की आपूर्ति को लेकर जमाखोरी, परिवहन या वितरण में गड़बड़ी है, तो उस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शी एवं जवाबदेही के लिए संवाद जरूरी है, सार्वजनिक क्षेत्र में और मंदिर इत्यादि में जहां लंगर इत्यादि गरीबों के लिए चलाए जाते हैं वहां पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। यदि सरकार का दावा सही है, गैस की कमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनता को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई है? इस प्रश्न का स्पष्ट और ईमानदार उत्तर देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। गैस संकट का वास्तविक समाधान तभी हो सकता है,

जब सभी पक्ष ईमानदारी के साथ वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपस में सहयोग करें। गैस, पेट्रोल, डीजल अब सभी लोगों से नियमित रूप से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और ना ही इसे झुठलाया जा सकता है। सभी पक्ष जितनी जल्दी हकीकत को समझ लेंगे, समस्या का समाधान उतनी ही जल्दी निकाल पाएंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पश्चिम एशियाई तनाव से प्रभावित हो सकता है भारतीय टायर निर्यात

- भू-राजनीतिक संकट का असर, एटमा ने सरकार से समर्थन की मांग की

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारतीय टायर उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटमा) ने चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष से टायर निर्यात प्रभावित हो सकता है। एटमा के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट और स्वेज नहर जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों में अस्थिरता यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका को होने वाली खेपों में देरी और ढुलाई लागत में बढ़ोतरी कर सकती है। भारत पश्चिम एशिया को सालाना लगभग 25-26 करोड़ डॉलर के टायर निर्यात करता है। यदि तनाव बढ़ता रहा, तो इन खेपों में व्यवधान आ सकता है। एटमा ने यह भी कहा कि निर्यात में अनिश्चितताओं के कारण भारतीय टायर उद्योग की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हो सकती है। टायर उत्पादन में कच्चे तेल से बने उत्पादों का 60-70 प्रतिशत हिस्सा होता है। प्रमुख इनपुट में सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक, प्रोसेसिंग ऑयल और टायर कॉर्ड फैब्रिक शामिल हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव (लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल) सीधे उत्पादन लागत बढ़ा रहे हैं। इस कारण माल ढुलाई और लॉजिस्टिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। एटमा के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि बढ़ती उत्पादन लागत, निर्यात अनिश्चितताएं और ढुलाई में रुकावट का मिला-जुला असर उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि समय पर नीतिगत समर्थन जरूरी है ताकि भारत की निर्यात गति बनी रहे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका प्रभाव बनाए रखा जा सके।

भारत में 2020-2026 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में तेज़ी, करोड़ों रोजगार के अवसर- मांझी

- सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं चलाई

नई दिल्ली । केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने संसद में बताया कि 2020 से 28 फरवरी, 2026 तक करीब 7.83 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत हुए हैं। इन उद्यमों से 34.50 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस अवधि में लगभग 1.37 लाख उद्यम बंद हुए, जिनमें मालिक बदलना, दोहरा पंजीकरण, प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना या व्यवसाय बंद होना मुख्य कारण रहे। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एसआरआई कोष, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और एमएसएमई चैंपियंस योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग किया जाता है। कोविड-19 महामारी के समय व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना लागू की गई। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक रही, जिसमें 1.13 करोड़ एमएसएमई को गारंटी दी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख खाते बचाए गए, जिनमें 98.3 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यम थे। पीएमईजीपी के लाभार्थियों में 39 प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाओं को गैर-विशेष श्रेणी की तुलना में अधिक सब्सिडी (35 फीसदी) दी जाती है। इसके अलावा, एमएसएमई की स्थिति में सुधार होने पर तीन वर्षों के लिए गैर-कर लाभ भी प्रदान किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें सरकार 10,000 करोड़ और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल 40,000 करोड़ का योगदान कर रही है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को विकास पूंजी उपलब्ध कराना है।

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं

जमा, निकासी और एटीएम जैसी बुनियादी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी-

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि भारत में लगभग 72 कर-ोड़ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) हैं, जिनमें न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है। इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) के तहत खोले गए खाते भी शामिल हैं। इन खातों में जमा, निकासी और एटीएम जैसी बुनियादी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छोटे जमाकर्ताओं और उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है जो अब तक इन सुविधाओं से दूर थे। जहां जीरो बैलेंस खातों पर राहत है, वहीं सामान्य बचत और चालू खातों में मासिक औसत बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। यदि ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं, तो बैंक उचित और पारदर्शी शुल्क लगा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने वाले ग्राहकों से 8,092.83 करोड़ रुपये वसूले। यह राशि बैंकों की कुल कमाई का केवल 0.3 प्रतिशत है और इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि सेवाओं के खर्च को संतुलित करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसी राह पर चलते हुए 2025 तक 9 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी जुर्माने हटा दिए या उनमें भारी कटौती की। यह कदम बैंकिंग सेवाओं को ग्राहक-केंद्रित और संवेदनशील बनाने की दिशा में उठाया गया।

एचएफसीएल को वैश्विक कंपनी से 10,159 करोड़ का ऑप्टिकल फाइबर ठेका

नई दिल्ली । भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी एचएफसीएल लिमिटेड को ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी से लगभग 10,159 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। कंपनी ने यह जानकारी शुक्रवार को शेयर बाजार में दी। यह ठेका 2026 से दिसंबर 2030 तक पांच वर्षों के लिए है। एचएफसीएल ने बताया कि यह समझौता उसकी विदेश स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। ठेके के तहत कंपनी उच्च गुणवत्ता और उच्च फाइबर क्षमता वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति करेगी। कुल संभावित मूल्य लगभग 1.10 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 10,159 करोड़ रुपये) है। एचएफसीएल ने ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। कंपनी ने बताया कि यह पहला **दीर्घकालिक और बहुवर्षीय ऑप्टिकल फाइबर केबल आपूर्ति समझौता है, जिसे एचएफसीएल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस समझौते के तहत एचएफसीएलग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार केबल की आपूर्ति करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह ठेका कंपनी को वैश्विक बाजार में पकड़ मजबूत करने और भविष्य में बड़े अंतरराष्ट्रीय ठेकों के अवसर खोलने में मदद करेगा।

गोल्ड लोन में राहत, माइक्रोफाइनेंस कंपनियां तेजी से बदल रहीं पोर्टफोलियो

- सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के परिपक्व होने के साथ ही विविधीकरण की प्रवृत्ति में और तेजी की संभावना

नई दिल्ली ।

सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआईएस) बाहरी दबावों के कारण मुख्य रूप से परिसंपत्ति गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक-राजनीतिक माहौल और राज्यों के कड़े नियम जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, असम और कर्नाटक में जबरन वसूली पर रोक ने इन संस्थानों को अपनी रणनीतियों में बदलाव के लिए प्रेरित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कुल परिसंपत्तियों पर 60 प्रतिशत तक पात्रता मानदंड में ढील देने के बाद, सूक्ष्म वित्त संस्थान अब सुरक्षित ऋण उत्पादों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इन उत्पादों में स्वर्ण ऋण, गृह सुधार ऋण, वाहन ऋण और संपत्ति के बदले ऋण शामिल हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सैटिन क्रेडिटकेयर, स्पंदना स्फूर्ति जैसी संस्थाओं ने अपने पारंपरिक सूक्ष्म ऋणों में कमी की है। यह कदम जोखिम कम करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। सूक्ष्म वित्त संस्थान अब एमएसएमई ऋण, एलएपी, किफायती आवास वित्त और वाहन ऋण जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहे हैं। सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क के एक अे धिकारी ने कहा कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के परिपक्व होने के साथ ही विविधीकरण की प्रवृत्ति में और तेजी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एमएफआईएस के संचित स्वामित्व (एयूएम) में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है, जबकि सहायक कंपनियों में 40-50 प्रतिशत की तेजी देखी जा रही है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1470, निफ्टी 488 अंक गिरा

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही बिकवाली हावी होने से आयी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढने से भी निवेशकों ने बाजार से दूरी बनायी है जिससे भी घरेलू बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1470.50 अंक की गिरावट के साथ ही 74,563.92 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 488.05 अंक फिसलकर यह 23,151.10 के स्तर पर बंद हुआ। आज बाजार में आई गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे।

शेयर मार्केट में गिरावट के कारण निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। बीएसई सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण सुबह-सुबह करीब 6.55 लाख करोड़ रुपए गिर कर करीब 433 लाख करोड़ रुपए रह गया है। बाजार जानकारों के अनुसार मध्यपूर्व में संघर्ष के कारण तेल के दाम बढ़ने से भी बाजार गिरा

है। वहीं अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट से भी भारतीय बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों करीब 7,500 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को कुछ सहारा देने की कोशिश की। आज आईटी, मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में व्यापक बिकवाली देखने को मिली। इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स गिरावट के साथ ही 75,444 अंक पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 76,034 अंक पर बंद हुआ था। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 588.06 अंक की गिरावट के साथ 75,446.36 अंक पर कारोबार करता दिखाई दिया। इसी तरह निफ्टी भी गिरावट के साथ 23,462 अंक पर खुला। सुबह शुरुआत के बाद यह 216.35 अंक की कमजोरी के साथ लगभग 23,422 अंक पर कारोबार कर रहा था। गिरावट की एक बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली भी है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया है। सेक्टोरल स्तर पर मेटल, आईटी और बैंकिंग शेयरों में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर नकारात्मक असर

एलपीजी की कमी से घरों में फिर लौट आया केरोसिन

- सरकार ने वैकल्पिक उपाय किए लागू

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव ने वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत विदेशों से खरीदता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई बाधित होने के कारण घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर असर पड़ा। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी, जिससे होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति कम हो गई। सरकार ने गैस की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाया। होटल और रेस्तरां को कोयला और बायोमास जलाने की अस्थायी छूट मिली, जबकि घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन का अतिरिक्त कोटा जारी किया गया। राज्यों को नियमित कोटे के ऊपर 48,000 किलोलीटर मिट्टी का तेल दिया गया। एलपीजी की कमी की अफवाहों के कारण बुकिंग में उछाल आया। इसे रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी वाले सिलेंडर की अगली बुकिंग अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 45 दिन की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह सीमा 25 दिन रखी गई। वर्तमान में देश में एलपीजी की डिलीवरी का औसत समय 2.5 दिन है और घरेलू उत्पादन में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केरोसिन कभी हर घर में उपयोग होता था, लेकिन 2013-14 से 2022-23 के बीच इसके उपयोग में सालाना 26 प्रतिशत गिरावट आई।

बिजली, सोलर पैनल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ ऊर्जा नीति इसके मुख्य कारण रहे। दिल्ली 2014 में केरोसिन-मुक्त शहर घोषित हुआ। मार्च 2026 में केरोसिन की कीमतें 46-90 रुपये प्रति लीटर रही, औद्योगिक ग्रेड की कीमत प्रायः अधिक है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 12 पैसे टूटकर 92.37 पर बंद हुआ। आज शुरुआती कारोबार में रुपया अपने दिन के रिकॉर्ड निचले स्तर 92.36 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। बाजार के जानकारों ने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कोई संकेत न दिखने के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मजबूत रुख, विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोर रुझान ने रुपये पर और दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 92.33 प्रति डॉलर पर खुला। फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने दिन के रिकॉर्ड निचले स्तर 92.36 पर पहुंच गई जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया गुरुवार को कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.36 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया था। सत्र के अंत में 24 पैसे टूटकर अपने सबसे निचले स्तर 92.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 फीसदी की बढ़त के साथ 99.77 पर रहा।

केरल में एलपीजी संकट से रेस्तरां और कैटरिंग सेवाएं ठप

- करीब 40 प्रतिशत रेस्तरां बंद होने की कगार पर

कोच्चि (ईएमएस)। केरल में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण एलपीजी की कमी ने खाने-पीने के उद्योग को प्रभावित किया है। केरल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार, राज्य में लगभग 40 फीसदी रेस्तरां बंद होने की स्थिति बन रही है। शहरी क्षेत्रों के होटल और रेस्तरां सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि वहां लकड़ी या अन्य ईंधन से खाना बनाना व्यावहारिक नहीं है। प्राइवेट एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें दोगुनी तक पहुंच गई हैं। कासरगोड में 17 किलोग्राम का सिलेंडर 3,000 रुपये में बिक रहा है, जबकि सामान्य 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत करीब 1,800 रुपये है। लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे वैकल्पिक खाना पकाने की व्यवस्था कठिन हो गई है। एलपीजी संकट ने रेस्तरां के अलावा कैटरिंग सेवाएं, छात्रावास की मेस, कैंटीन और शवदाह गृह भी प्रभावित किए हैं। राज्य में शादी का मौसम शुरू होने वाला है, जिसके कारण कैटरिंग बुकिंग पहले ही हो चुकी हैं। मुस्लिम और ईसाई समुदायों के निकाह और लेंट/चालीसा काल की समाप्ति के बाद शादी समारोहों पर भी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने और प्राथमिकता तय करने का निर्णय लिया गया। अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, स्कूल, सामुदायिक रसोई और आईटी/फैक्ट्री कैंटीनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, वैकल्पिक ईंधन जैसे मिट्टी का तेल की आपूर्ति बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर पहले चेतावनी दी जाती तो कई रेस्तरां वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे।

एफटीएक्स 2026 कार्यक्रम में लॉन्च हुआ नया एआई प्लेटफॉर्म

नई दिल्ली ।

डिजिटल पेमेंट कंपनी रेजरपे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका उद्देश्य कारोबारों के भुगतान ढांचे के निर्माण और प्रबंधन के तरीके को बदलना है। कंपनी ने अपने वार्षिक कार्यक्रम रेजरपे एफटीएक्स 2026 में दुनिया का पहला एजेंट स्टूडिया लॉन्च किया, जो एआई एजेंट्स के माध्यम से पेमेंट ऑपरेशन्स को अधिक स्मार्ट और स्वचालित बनाने में मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म एंथ्रो पिक के क्लाउड एजेंट एसडीके पर आधारित है और इसे ऑनलाइन व्यापारियों को जोड़ने, भुगतान एकीकरण को आसान बनाने तथा संचालन प्रबंधन को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कंपनी ने इसके साथ एक नई एजेंटिक एक्सपीरियंस लेयर भी पेश की है, जो व्यवसायों को अपने भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम बनाएगी। रेजरपे के एक अे धिकारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज कारोबारों को केवल अधिक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी बुद्धिमान तकनीक की आवश्यकता है जो खुद काम कर सके। उनके अनुसार एजेंट स्टूडियो के जरिए कंपनियां ऐसे

एआई एजेंट्स तैनात कर सकेंगी जो उनके राजस्व प्रवाह को समझने और उसकी निगरानी करने के साथ-साथ भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी कर सकेंगे। ये एजेंट अरबों लेनदेन का रियल-टाइम विश्लेषण भी करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य यह है कि व्यवसाय अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि भुगतान से जुड़े तकनीकी काम पृष्ठभूमि में सहज रूप से चलते रहें। उनका मानना है कि यह तकनीक वित्तीय संचालन के एक नए चरण की शुरुआत है, जहां इंटेलिजेंट एजेंट्स टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं, एंथ्रो पिक इं डिया के अे धिकारी ने कहा कि एआई एजेंट्स राजस्व वसूली, विवाद समाधान और नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान जैसी वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी के भाव में सुस्ती

- सोने का भाव 1.60 लाख, चांदी लगभग 2.66 लाख रुपए प्र ति किलो

नई दिल्ली। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिली। दोनों धातुओं की कीमतें आज गिरावट के साथ खुलीं और कारोबार के दौरान भी दबाव में रहीं। घरेलू कमोडिटी बाजार मल्टी कमो डिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल वायदा कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,251 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 1,60,271 रुपये था। इस समय यह कॉन्ट्रैक्ट 93 रुपये की गिरावट के साथ करीब 1,60,178 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान सोने ने 1,60,251 रुपये का दिन का उच्च स्तर और 1,59,764 रुपये का निचला स्तर छुआ। इस वर्ष सोने के वायदा भाव 1,80,779 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। चांदी के वायदा भाव में भी आज कमजोरी देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मई कॉन्ट्रैक्ट 1,961 रुपये की गिरावट के साथ 2,66,001 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 2,67,962 रुपये था। इस समय यह 1,613 रुपये की गिरावट के साथ लगभग 2,66,349 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान चांदी ने 2,66,888 रुपये का उच्च स्तर और 2,66,001 रुपये का निचला स्तर दर्ज किया। इस साल चांदी के वायदा भाव 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं में नरमी का रुख बना हुआ है। वैश्विक कमोडिटी बाजार कॉमेक्स पर सोना 5,084 डॉलर प्रति औंस पर खुला, जबकि पिछले सत्र में इसका बंद भाव 5,125.80 डॉलर था। इस समय सोना 8.90 डॉलर की गिरावट के साथ 5,116.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोना 5,586.20 डॉलर प्रति औंस का उच्च स्तर छू चुका है। वहीं चांदी 83.91 डॉलर प्रति औंस पर खुली और कारोबार के दौरान 0.60 डॉलर की गिरावट के साथ करीब 84.51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इस वर्ष चांदी का उच्चतम स्तर 121.79 डॉलर प्रति औंस रहा है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में रेमिटेंस में तेजी: उद्योग विशेषज्ञ

पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय अपने परिवारों को अधिक पैसा भेज रहे

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के बीच मार्च में भारत में रेमिटेंस में असामान्य तेजी देखी गई है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य महीनों की तुलना में यह लगभग 20-30 प्रतिशत अधिक है। पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय अपने परिवारों को अधिक पैसा भेज रहे हैं, जिससे भारत में प्रवासी रेमिटेंस में वृद्धि हुई है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट ने रेमिटेंस का मूल्य और बढ़ा दिया है।

श्चिम एशियाई तनाव शुरू होने के बाद से रुपये में 1.32 प्रतिशत की गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब 92 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच गया है, जबकि तनाव से पहले यह लगभग 91 रुपये था।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट ने रेमिटेंस की वास्तविक कीमत बढ़ाने में मदद की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वृद्धि अल्पकालिक है। यदि संघर्ष लंबा चला और नौकरियों में कटौती हुई, तो भारत में रेमिटेंस की आवक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

खासकर आतिथ्य और निर्माण क्षेत्र पर इसका असर ज्यादा होगा। निजी बैंक और स्मॉल फाइनैंस बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मार्च में रेमिटेंस में 15-30 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिति के लिए सावधानी जरूरी है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेमिटेंस का प्रमुख स्रोत अमेरिका है, जो कुल आवक का 27.7 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद यूएई (19.2 फीसदी), ब्रिटेन (10.8 फीसदी), सऊदी अरब (6.7 फीसदी) और सिंगापुर (6.6 फीसदी) का स्थान है।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में प्रवासी भारतीयों ने 107 अरब डॉलर से अधिक भेजे हैं। तुलना के लिए, वित्त वर्ष 2025 में 132 अरब डॉलर और 2024 में 117 अरब डॉलर भेजे गए थे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हॉकी विश्वकप 2026: खिताब जीतने पर भारतीय महिला टीम का ध्यान, सेमीफाइनल में इटली की चुनौती

हैदराबाद (एजेंसी)। एफआईएच हॉकी महिला विश्वकप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय टीम घरेलू दर्शकों के सामने इटली के खिलाफ शुक्रवार को सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट के खिताब की ओर कदम बढ़ाने उतरेगी। भारतीय टीम पूल बी में तीन मैचों में सात पॉइंट्स और स्कॉटलैंड पर बेहतर गोल डिफरेंस के साथ शीर्ष पर है। मेजबान टीम ने पूल स्टेज में दो जीत और एक ड्रॉ दर्ज किया।

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत उरुग्वे के खिलाफ 4-0 की जबरदस्त जीत के साथ की। अपने दूसरे मैच में, उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-2 से करीबी मुकाबला ड्रॉ खेला और फिर वेल्स पर 4-1 की आसान जीत के साथ ग्रुप स्टेज खत्म किया। पूल स्टेज में शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने टूर्नामेंट के नियम के तहत एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना क्वालिफिकेशन पक्का कर लिया, जिसके तहत दो क्वालिफाइंग इवेंट्स में चौथे नंबर पर रहने वाली दुनिया की सबसे ऊंची रैंक वाली टीम को वर्ल्ड कप में जगह मिलती है।

क्वालिफायर्स का सैंटियागो लेग पहले खत्म हो गया था, जहां चिली, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड ने तीन डायरेक्ट क्वालिफिकेशन स्पॉट हासिल किए थे। जापान सैंटियागो में चौथे नंबर पर रहा और अभी दुनिया में 15वें नंबर पर है। दुनिया भर नौवें नंबर की टीम मेजबान भारत ने कम से कम यह पक्का कर लिया है कि वे दोनों टूर्नामेंट्स में सबसे ऊंची रैंक वाली चौथी टीम के तौर पर खत्म करेंगे, जिससे विश्व कप के लिए उनका टिकट पक्का हो गया है। अब उसका मकसद अपनी लय बनाए रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगा।

फाइनल में भारत का मुकाबला इटली से होगा। इटली पूल ए में चार अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहा है, जिसने एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार दर्ज की है, जिससे मेजबान टीम को सेमीफाइनल से पहले थोड़ी साइकोलॉजिकल बढ़त मिली है। भारत की फॉरवर्ड नवनीत कौर के शानदार फॉर्म को भी आगे बढ़ाना चाहेगा, जो अभी चार गोल के साथ टूर्नामेंट की संयुक्त शीर्ष स्कोरर हैं। उन्होंने वेल्स के खिलाफ आखिरी पूल मैच में हैट्रिक बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था।

वहीं इटली की बात की जाए तो वह फेडेरिका काटर पर निर्भर रहेगा, जो उनकी मुख्य अटैकिंग खिलाड़ी रही हैं और उन्होंने अब तक इस कॉम्पिटिशन में तीन गोल किए हैं। हेड-टू-हेड मुकाबलों की बात करें तो, भारत और इटली 2012 से सात बार एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं। भारत ने उनमें से पांच मैच जीते हैं, जबकि इटली ने एक जीत दर्ज की है और एक गेम ड्रॉ रहा है, जिससे मेजबान टीम को सेमीफाइनल से पहले थोड़ी साइकोलॉजिकल बढ़त मिली है।

सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा, 'एफआईएच हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिपुाई करना इस ग्रुप के लिए एक जरूरी माइलस्टोन है, और प्लेयर्स ने टूर्नामेंट में अब तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके लिए वे बहुत क्रेडिट की हकदार हैं। उन्होंने पूरे पूल स्टेज में अच्छा डिसिप्लिन, कॉम्पोजर और अटैकिंग इंटेंट दिखाया है।

इटली एक कॉम्पिटिटिव टीम है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाया है कि वे मजबूत टीमों को परेशान कर सकते हैं। हमारे लिए, फोकस अपने प्लान को अच्छी तरह से एग्जिक्यूट करने, अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखने और उसी ऊर्जा और विश्वास के साथ खेलते रहने पर होगा।' भारतीय महिला टीम शुकवार को शाम सात बजकर 30 मिनट पर सेमीफाइनल में इटली से भिड़ेगी।

वैभव को एशियाई खेलों के लिए मिल सकती है भारतीय टीम में जगह

इंडियन वेल्स (एजेंसी)। मुम्बई (ईएमएस)। उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम से डेब्यू का अवसर मिल सकता है। इसका कारण है कि इस साल भारतीय टीम का काफी व्यस्त कार्यक्रम है और उसे अपनी धरती के साथ ही विदेशी मैदानों पर भी काफी क्रिकेट खेलना है। इसी को देखते हुए ये भी हो हो सकता है भारतीय बोर्ड दो टीमें उतारे जिस एक अनुभवी और दूसरी युवा क्रिकेटरों से भरी रहेगी। उसे जून से लेकर अक्टूबर तक लगाता कई टीमों से खेलना है। इसी दौरान उसे जिम्बाब्वे के अलावा नई टीम आयरलैंड से भी खेलना है। वैभव ने पिछले कुछ समय से भारतीय अंडर 19 के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी को देखते हुए उन्हें इस साल के अंत में एशियाई खेलों में उतरने का अवसर मिल सकता है।

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम को जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन एकदिवसीय मुकाबले खेलने हैं, जिसके बाद जुलाई में वह सीमित ओवरों के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। भारतीय टीम इस दौरान 5 टी20 के साथ ही 3 एकदिवसीय मैच खेलेगी। इसके अलावा इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच दो नए दौरे भी जुड़ सकते हैं। इंग्लैंड पहुंचने से पहले भारत डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की छोटी सीरीज खेल सकता है। वहीं श्रीलंका क्रिकेट समुद्री तूफान 'दित्वह' से हुए नुकसान की कमी पूरी करने के लिए भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों से पहले तीन टी20 मैच खेलने का अनुरोध कर सकती है।

आईसीसी ने टी20 विश्वकप विजेताओं पर की इनामों की बारिश, भारतीय टीम को मिले 24 करोड़

-उपविजेता न्यूजीलैंड को मिले 13 करोड़ रुपये

दुबई (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पुरुष टी20 विश्वकप 2026 के लिए इनामी राशि घोषित कर दी है। टूर्नामेंट में कुल 11.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब (1 अरब, 39 करोड़, 4 लाख, 43 हजार) की इनामी राशि दी गयी है। इस बार की इनामी राशि पिछली बार से अधिक है। इसमें विजेता भारतीय टीम को 2.63 मिलियन डॉलर करीब 24.3 करोड़ रुपये जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को 26,39,423 अमेरिकी करीब 13 करोड़ की इनामी राशि मिली है। वहीं सेमीफाइनल हारने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को 10,05,577 डॉलर करीब 9 करोड़ रुपये और इंग्लैंड की टीम को 9,74,423 डॉलर करीब 8 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं सुपरआठ की चार टीमों, वेस्टइंडीज को 5,38,269 डॉलर करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपये। वहीं पाकिस्तान 4,91,538 डॉलर करीब 4 करोड़ 80 लाख। जिम्बाब्वे को 4,91,538 डॉलर करीब 4 करोड़ 51 लाखा, श्रीलंका को 475,962 डॉलर करीब 4 करोड़ 37 लाख रुपये मिलेंगे।

इस बीच, जो टीमें सुपर 8 स्टेज तक पहुंचीं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाईं, जिनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हैं, उनमें से प्रत्येक टीम को 3,09,808 डॉलर दिए जाएंगे। 2 करोड़ 85 लाख रुपये दिये जाएंगे।

शेष प्रतिभागियों में स्कॉटलैंड को 2,78,654 डॉलर करीब 2 करोड़ 56 लाख और आयरलैंड को 2,71,731 डॉलर करीब 2 करोड़ 49 लाख रुपये मिलेंगे। इस बीच, इटली, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड अरब अमीरात और नेपाल को 2,56,154 डॉलर करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले स्टेज में बाहर हो होने वाली कनाडा, नामीबिया और ओमान की टीमों को 2,25,000 डॉलर करीब 2 करोड़ 6 लाख का इनाम लाग लेने के लिए दिया गया है।

पिछले विश्वकप की तरह खेलते तो शायद ही जीत मिलती: सूर्यकुमार

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का मानना है कि समय के साथ ही खेल की रफ्तार भी बदल रही है, ऐसे में आक्रामक अंदाज अपनाना सफल रहा। वहीं अगर अगर भारतीय टीम पिछले टी20 विश्व कप की तरह खेलती तो उसे इसबार शायद ही जीत मिलती। सूर्या का कहना है कि पिछली बार जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के समय भारतीय टीम जीती थी तब हालात अलग थे। वहीं अब अलग हैं।

कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारतीय टीम का खेल बेहद संतुलित और अनुभव पर आधारित माना जाता था। यह रणनीति 2024 तक प्रभावी रही पर दो साल बाद टी20 क्रिकेट की बदलती मांगों के सामने यह थोड़ी धीमी और पारंपरिक लगने लगी। इसी कारण सूर्यकुमार और

मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस बार खिलाड़ियों को निडर होकर खेलने को कहा। इससे टीम में यह साफ संदेश दिया गया कि अब कोई भी खिलाड़ी निजी उपलब्धियों के पीछे न जाकर टीम की जीत के लिए खेलेगा। इसी कारण जरूरत के अनुसार किसी भी खिलाड़ी को किसी भी क्रम पर उतारा गया। सूर्यकुमार ने कहा, हमें पता था कि 2024 टी20 विश्व कप में जिस तरह का क्रिकेट हमने खेला था, वह आगे काम नहीं करेगा। इसलिए हमने तय किया कि अब व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान सिर्फ मैच जीतना होगा। इसी कारण सेमीफाइनल तक हमारे किसी भी खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा रन बनाने वालों या सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में नहीं था पर इसके बाद भी हम जीत रहे थे। इस कारण है कि हर खिलाड़ी योगदान दे रहा था। उन्होंने आगे कहा कि इस सोच को टीम में शुरू से ही मजबूत करना जरूरी था।वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से भी माना है कि साल 2024 और 2026 की टीमों के बीच अंतर था। उनका मानना है कि 2024 की टीम अनुभव से भरी थी पर उसमें इतनी आक्रामकता नहीं थी। तब रोहित आक्रामक होकर खेलते थे जबकि विराट एक छोर संभाले रहते थे। वहीं अब टीम में कम अनुभव वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनमें आक्रामकता और आत्मविश्वास भरा हुआ है। टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ी संतुलन लाते हैं, जबकि अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी अपनी अलग शैली के साथ विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं।

शुभमन के लिए टी20 टीम में वापसी संभव नजर नहीं आती : आकाश चोपड़ा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि बल्लेबाज शुभमन गिल को टी20 टीम में जगह मिलने की कोई संभावना नहीं है। आकाश के अनुसार शुभमन की बल्लेबाज टी20 के अनुरुप नहीं है और ऐसे में उन्हें इसमें कप्तानी मिलने की उम्मीद तो करनी ही नहीं चाहिये। आकाश के अनुसार उनके लिए तो इस सबसे छोटे प्रारुप में जगह बनाना भी मुश्किल है। शुभमन अभी टेस्ट और एकदिवसीय टीम के कप्तान हैं। वह पिछले साल टी20 में वापसी में सफल रहे थे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाये। एशिया कप में उन्हें उपकप्तान बनाया गया था पर वह टीम को आक्रामक शुरुआत नहीं दे पाये। वह वापसी के बाद 15 मैचों में एक बार भी पचास रन नहीं बना पाये। इसी कारण उन्हें टी20 विश्वकप के लिए जगह नहीं मिली थी। शुभमन ने भारतीय टीम की ओर से 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 869 रन बनाये हैं। इस दौरान उनका औसत 28.03 और स्ट्राइक रेट 138.59 का रहा। आकाश ने कहा,शुभमन के लिए वापसी बेहद कठिन है। भारतीय टीम की बड़ी सोच थी कि तीनों प्रारुपों का एक कप्तान होना चाहिए ताकि आसानी हो पर ये संभव नहीं दिखता। वह टेस्ट और एकदिवसीय के कप्तान हैं लेकिन टी20 की कप्तानी नहीं मिल सकती। इस समय तो भारत की टी20 टीम में जगह मिलना भी कठिन है। अभी भारतीय टीम जिस अंदाज में खेल रही है। उसको देखते हुए बड़े स्कोर के लिए आक्रामक बल्लेबाजों की जरुरत होती है। ऐसे में उन्हें इस प्रारुप के प्रयास में एकदिवसीय की लय नहीं खोनी चाहिये। वहीं टीम से बाहर किए जाने के बाद शुभमन ने कहा था कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और जब भी अवसर मिलेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देने की कोशिश करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा टी20 विश्वकप का अगला सत्र

मुम्बई। आईसीसी टी20 विश्वकप का 11 वां सत्र अब साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रुप से खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 21 अक्टूबर से 19 नवंबर, 2028 के बीच होगा। इस प्रकार साल 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार इस वैश्विक इवेंट की मेजबानी का अवसर मिलेगा। वहीं न्यूजीलैंड में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। टूर्नामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी डेम थेरेसी वॉल्श के पास है। वाल्श के अनुसार ये मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी), सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी), एडिलेड ओवल और पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के ईडन पार्क, वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम और क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में होंगे।. इसमें 20 टीमें भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में भी आईसीसी का साल 2024 का ही प्रारुप लागू रहेगा। इस टूर्नामेंट के लिए 12 टीमों को स्थान मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मेजबान होने के कारण पहले ही जगह मिल गयी है। वहीं इस साल की विजेता भारतीय टीम के अलावा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे. को भी इसमें रैंकिंग के आधार पर जगह मिली है। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड को भी शामिल किय गया हैं। वहीं बचे 8 स्थानों के लिए रीजनल क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट इस साल के बीच में शुरू होंगे। अमेरिका और यूरोप में उप-रीजनल क्वालीफायर आयोजित किए जाएंगे, जिससे एसोसिएट देशों को भी 20 टीमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

धोनी का निचले क्रम पर उतरना सहित नहीं : पुजारा

चेन्नई। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी भले ही 44 साल के हो गये हैं पर इसके बाद भी उनके खेलने से चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को लाभ ही होगा। पुजारा के अनुसार धोनी अगर 20 से 30 गेंदों का भी सामन करते हैं तो भी वह मैच बदल सकते हैं। गौरतलब है कि बढ़ती उम्र और फिटनेस की दिक्कतों के कारण धोनी पिछले कुछ समय से निचले क्रम पर ही उतर रहे हैं पर पुजारा का मानना है कि ये सही नहीं है। उनका कहना है कि धोनी का निचले क्रम पर खेलने का फैसला सही नहीं है। वह ऊपरी क्रम पर टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। पुजारा ने कहा, 'मुझे धोनी के नंबर 8 या 9 पर बल्लेबाजी करना सही नहीं दिखता क्योंकि आज भी उनकी बल्लेबाजी ऐसी है कि वह मैच का रुख मोड़ सकते हैं। निचले क्रम पर अगर वह सिर्फ 5 या 10 गेंद खेलकर ही प्रभावित कर सकते हैं तो 25 या 30 गेंदें खेलने पर तो तूफान ही मचा देंगे।.' पुजारा का मानना है कि धोनी जिस प्रकार के हिटर हैं उसको देखते हुए उन्हें ऊपरी क्रम पर भेजा जाना चाहिये। पुजारा ने कहा कि सीएसके के ड्रेसिंग रूम का माहौर काफी अच्छा रहता है। इसी कारण टीम और खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। खिलाड़ियों को मालूम होता है कि उनसे टीम किस प्रकार की उम्मीदें करती है। इसी कारण सीएसके में रहने वाला हमेशा उसके साथ बना रहता है। वहीं टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन के अनुसार हमेशा ही आईपीएल से पहले धोनी की फिटनेस और उनके हर मैच खेलने को लेकर भी अटकलें रहती हैं पर ये तय है कि वह अंतिम ग्यारह में बने रहेंगे।

कार्लोस अल्काराज लगातार पांचवीं बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे

इंडियन वेल्स (एजेंसी)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपनी जीत का सिलसिला 16 मैचों तक बढ़ाया और गुरुवार को बीएनपी परीबा ओपन में लगातार पांचवें इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। टॉप सीड खिलाड़ी ने कैमरन नॉरी के खिलाफ 6-3, 6-4 से जीत हासिल की, जिससे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाड़ी से बदला ले लिया, जिसने उन्हें पिछले नवंबर में पेरिस में हराया था।

अल्काराज ने कोर्ट पर अपने इंटरव्यू में नॉरी के बारे में कहा, 'मुझे उनके स्टाइल से बहुत दिक्कत होती है। हर बार जब मैं उनके खिलाफ खेलता हूं तो यह मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है। उनके स्टाइल, उनके (हैवी) टॉपस्पिन फोरहैंड, सुपर हाई के साथ यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। और फिर बैकहैंड, बहुत फ्लैट और बहुत लो। कभी-कभी उनके खिलाफ खेलना मुश्किल होता है। मुझे सही शॉट मिल रहा है। मैंने अच्छा खेला। मैंने सॉलिड खेला। जब भी हो

सका, मैंने एग्रेसिव खेला। मैं इस लेवल पर खेलकर खुश हूं।'

अल्काराज और नॉरी ने पूरे मैच में मोमेंटम बदला, लेकिन स्पेन के खिलाड़ी ने ज़्यादातर अपना पलड़ा भारी रखा। पहला सेट आखिरी चार गेम में तीन बार सर्व ब्रेक के साथ खत्म हुआ। इसके बाद नॉरी ने दूसरे सेट में 2-0 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अल्काराज ने लगातार चार गेम जीतकर जवाब दिया। 22 साल के खिलाड़ी ने 10 ब्रेक के मौके बनाए, जिनमें से चार को भुनाया। तेज बेसलाइन हिटिंग, हल्के ड्रॉप शॉट और शानदार नेट प्ले का मिक्स दिखाते हुए, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने एक घंटे 33 मिनट में जीत हासिल की।

अल्काराज ने कहा, 'टेनिस लगभग आधे सेकंड में सही शॉट चुनने के बारे में है,' जिन्होंने 19 फोरहैंड विनर के साथ गेम खत्म किया। 'कभी-कभी मैं शॉट मिस कर देता हूँ क्योंकि मैंने सही वाला नहीं चुना होता। मेरे दिमाग में, मेरे पास सात, पाँच ऑप्शन होते हैं, कभी-कभी मेरे लिए सही वाला चुनना मुश्किल होता है।'

अपनी जीत के साथ, अल्काराज लगातार पांच इंडियन वेल्स सेमीफ़ाइनल में पहुंचने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए, उनके हमवतन राफेल नडाल (2006-13) और विरोधी नोवाक जोकोविच (2011-16) ही उनसे आगे हैं। अल्काराज हेड2हेड सीरीज में नॉरी से 6-3 से आगे हैं। 26 बार के टूर-लेवल टाइटलिस्ट सेमीफाइनल में दानिल मेदवेदेव के खिलाफ अपने 6-2 के रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगे। अल्काराज ने मेदवेदेव के साथ अपने पिछले चार मुकाबले जीते हैं। अल्काराज ने 2023 और 2024 में इंडियन वेल्स का खिताब जीता, दोनों फाइनल में मेदवेदेव को हराया।

रंकीरेड्डी के कंधे में दर्द के कारण उनकी और चिराग की जोड़ी स्विस ओपन से हटी

बासेल। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी के कंधे में दर्द के कारण उनकी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष जोड़ी ने शुक्रवार को स्विस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। इस सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम आठ युगल मुकाबलों में रंकीरेड्डी और शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन फॉस्ट कजेर और रासमस कजेर से होना था। बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश से सुर्खियां बटोरने वाले अमलापुरम के 25 वर्षीय रंकीरेड्डी अपने दाहिने कंधे की समस्या से जूझते रहे हैं। रंकीरेड्डी ने 2023 में बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी गति 565 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारतीय टीम के मलेशिया मूल के कोच टैन किम हर ने 'पीटीआई' को बताया, 'यह पुरानी चोट है। उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें कम से कम एक सप्ताह लगेगा।' समझा जा रहा है कि यह चोट नयी नहीं है और शीर्ष स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों में आम है। भारतीय जोड़ी ने बृहस्पतिवार को प्री-क्वार्टर फाइनल में जापान के हिरोकी ओकामूरा और क्योहेई यामाशिता के खिलाफ 74 मिनट के कड़े मुकाबले में 21-15, 15-21, 28-26 से जीत हासिल की। एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग अब सात से 12 अप्रैल तक होने वाली बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। भारतीय जोड़ी ने 2023 में खिताब जीता था।

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के सहायक कोच की भूमिका में नजर आयेंगे दहिया

अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को अपना नया सहायक कोच बनाया है। दहिया कोच के तौर पर काफी सफल रहे हैं। वह दो बार की खिताब विजेता कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) में भी सहायक कोच रहे है। इसके अलावा उनके कोच रहते ही दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी खिताब भी जीता था। अब देखना है कि गुजरात को दहिया से कितना लाभ मिलता है। इससे पहले टीम ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच नियुक्त था। ऐसे में दहिया को उनके साथ मिलकर टीम की बल्लेबाजी को निखारना होगा। गुजरात टाइटंस को उम्मीद है कि दाहिया के होने से टीम का कोचिंग स्टाफ और बेहतर तरीके से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर पायेगा। दहिया ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय के साथ ही दो टेस्ट मैच भारतीय टीम की ओर से खेले हैं। खेल से संन्यास के बाद वह कोच के तौर पर घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के साथ जुड़े रहे हैं। दहिया के कोच रहते ही साल 2007-08 सत्र में दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी खिताब जीता और उसके बाद से वह कई अन्य घरेलू और आईपीएल टीम के भी कोच रहे हैं। गुजरात की टीम आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम में से एक हैं। वह अपने शुरुआती चार सत्र में से तीन में प्ले ऑफ में पहुंची और उसने एक बार खिताब भी जीता है।

मैं सिर्फ टाइमिंग पर ध्यान देती हूं, मेडल्स पर नहीं : पैरालंपिक प्रीति पाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रीति पाल, जो पैरालंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, ने अपनी सफलता का राज बताया है। उनका कहना है कि वह सिर्फ अपनी टाइमिंग बेहतर करने पर ध्यान देती हैं और मेडल जीतने के बारे में सोचकर खुद पर दबाव नहीं डालतीं।

प्रीति ने 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे - एक महिलाओं की 100मी रेस में और दूसरा 200मी टी35 रेस इवेंट में। बुधवार को चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में महिलाओं की 100मी टी35/टी37 रेस में गोल्ड मेडल जीतने के बाद यूनीवार्ता से बात करते हुए प्रीति ने कहा, 'यह वह मुकाबला है जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। यहां बात मेडल की नहीं, बल्कि टाइमिंग की होती है। यहां मुकाबला करने आए सभी एथलीटों ने अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की है। मुझे तो यह भी लगता है कि मैं ठीक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा मैं ट्रेनिंग के दौरान कर रही थी।'

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 11 से 13 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जा रहा है जिसमें 8 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रीति ने रेस में गोल्ड मेडल जीतने के लिए 14.46 सेकंड का समय लिया। रूस की मार्गरीटा माताएवा 16.25 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि करीना माचुलस्काया ने 17.38 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

एक पैरा एथलीट के तौर पर उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन पर बात करते हुए इस स्प्रिंटर ने कहा कि चोटें एथलीटों के लिए सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बनी रहती हैं, खासकर तेज रफ्तार वाले स्पीड सेशंस के दौरान। 'कई दिक्कतें आई हैं, खासकर चोटें। चोटें तो हर एथलीट को लगती हैं। जब हम स्पीड सेशंस शुरू करते हैं, तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। रिकवरी बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे कोच हमें आइस बाथ (बर्फ के पानी में नहाना) दिलवाकर रिकवरी में मदद करते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा होता है।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि चोट-मुक्त रहने से एथलीट ट्रेनिंग, खान-पान और आराम पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं। मुकाबले की अपनी तैयारियों के बारे में प्रीति ने बताया कि पिछले एक महीने से ट्रेनिंग के दौरान वह अपनी अब तक की सबसे अच्छी टाइमिंग हासिल कर रही थीं। 25 साल की इस एथलीट ने खिलाड़ियों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए नेशनल ट्रेनिंग ग्रुप को श्रेय दिया।

प्रीति ने कहा, 'हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही है। नेशनल टीम में हम एक ग्रुप के तौर पर ट्रेनिंग करते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं। हमारे साथ सिमरन शर्मा जैसी एथलीट हैं, जो अर्जुन अवॉर्डविजेता और पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, और चिराग बरेठा हैं, जो पहले दुनिया में नंबर एक रैंक

पर थे। साथ में प्रैक्टिस करने से हम सभी को बेहतर बनने में मदद मिलती है।' आगे की ओर देखते हुए इस पैरा स्प्रिंटर ने कहा कि वह आने वाले इवेंट में और भी दमदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

200मी का इवेंट तीसरे दिन है और मैं उसमें अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती, मैं बस अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाना चाहती हूं।' यूपी की रहने वाली इस एथलीट का मानना है कि असली मुकाबला खुद से ही होता है और अपने ही पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।

सैमसन के होने से राजस्थान के खिलाफ पहले ही मुकाबले में भारी पड़ेगी सीएसके : इरफान पठान

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान के अनुसार आईपीएल में इस बार बल्लेबाज संजू सैमसन के आने का लाभ चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को मिलेगा। आईपीएल नीलामी के पहले ही ट्रेड डील के तहतर ही सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स से सैमसन को हासिल कर लिया था। पठान के अनुसार जिस प्रकार का जबरदस्त प्रदर्शन विश्वकप में सैमसन ने किया है। उससे वह काफी अच्छे फार्म में हैं। ऐसे में उनके होने भर से राजस्थान रॉयल्य के खिलाफ होने वाले शुरुआती मैच में सीएसके की टीम के पास जीत के अधिक अवसर रहेंगे। पठान के अनुसार, सैमसन लंबे समय तक रॉयल्स में शामिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें टीम की रणनीति के अलावा, खिलाड़ियों के खेलने के तरीके का भी अंदाजा है। इसका लाभ भी सीएसके को मिलेगा। सीएसके ने सैमसन को लगभग 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। वहीं इसके बदले में सैम कुरम और अनुभवी ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की टीम में चले गए। पठान के अनुसार सैमसन के होने से टीम को रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में काफी लाभ होगा। इसका कारण है कि सैमसन लंबे समय तक राजस्थान में रहे है और जानते हैं कि टीम केपावरप्ले में किस प्रकार खेलती है, बीच के ओवरों में उनकी रणनीति क्या होती है और गेंदबाजी संयोजन कैसे काम करता है।सीएसके अपना पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में खेलेगी। संजू सैमसन एक दशक से भी अधिक समय तक राजस्थान रॉयल्स का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2013 में टीम के साथ अपना सफर शुरू किया और जल्द ही टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हो गए। बाद में उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई। आईपीएल में सैमसन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 150 से ज्यादा पारियां खेलते हुए 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम दो शतक और कई अर्धशतक दर्ज हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से अधिक रहा है। ऐसे में वह लीग के सबसे बेहतर बल्लेबाजों में से एक हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

इराक के बसरा बंदरगाह पर हमला, तेल केंद्रों पर कामकाज रुका

बगदाद, एजेंसी। इराक के बसरा बंदरगाह पर एक बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस घटना के बाद देश के सभी तेल केंद्रों पर कामकाज रोक दिया गया है। इराक की सरकारी पोर्ट कंपनी के महानिदेशक फरहान अल-फरतौसी ने एक बयान में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह हमला फारस की खाड़ी में बसरा बंदरगाह के पास एक जहाज पर हुआ। जिस समय हमला हुआ, उस समय जहाज से सामान दूसरे जहाज पर भेजा जा रहा था। अभी यह साफ नहीं है कि हमला ड्रोन से हुआ या मिसाइल से। यह भी पता नहीं चला है कि हमला हवा से हुआ या पानी से। बचाव दल ने मौके से एक शव बरामद किया है और 38 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इराक के व्यापारिक बंदरगाह अभी खुले हैं। लेकिन तेल से जुड़े सभी टर्मिनलों को बंद कर दिया गया है।

इट हाउस के पास कार ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ा, सड़कों को बंद किया गया, ड्राइवर गिरफ्तार

वॉशिंगटन डीसी , एजेंसी। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास बुधवार तड़के एक वैन(कार) ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। घटना लाफायेट स्क्वायर के पास हुई। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने कहा कि संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही है। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। घटना के बाद व्हाइट हाउस के आसपास की कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में यातायात प्रभावित हुआ। मामले की जांच जारी है।

ईरान पर सैन्य कार्रवाई सही? घर में घिरे ट्रंप, सर्वे में अमेरिका के लोगों का चौंकाने वाला खुलासा

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका में जनता की राय बंटी हुई है। नए सर्वे बताते है कि

अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं और उन्हें डर है कि इससे देश पहले से अधिक असुरक्षित हो सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी साफ दिख रहा है जहां रिपब्लिकन मतदाता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के साथ खड़े हैं, वहीं डेमोक्रेट और स्वतंत्र मतदाता चिंता और विरोध में हैं। सर्वे रिपोर्ट में क्या सामने आया क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे में लगभग 53% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, जबकि 40% ने समर्थन किया और 10% ने स्पष्ट राय नहीं दी। इप्सोस, वाशिंगटन पोस्ट और ष्टहह के सर्वे में भी यही रुझान दिखा कि अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं। इसके विपरीत, फॉक्स न्यूज के सर्वे में मत लगभग बराबर बंटा हुआ दिखा, जहां आधे मतदाताओं ने समर्थन किया और आधे ने विरोध। सुरक्षा और तेल की कीमतों को लेकर चिंता क्विनिपियाक के सर्वे में 55% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान ने अमेरिका के लिए तत्काल कोई सैन्य खतरा पैदा किया। वहीं, फॉक्स न्यूज के सर्वे में 60% मतदाताओं ने माना कि ईरान अमेरिका के लिए वास्तविक खतरा है। अमेरिकियों को तेल और गैस की कीमत बढ़ने का डर भी सताता है। इप्सोस के 6-9 मार्च सर्वे में लगभग दो-तिहाई लोगों ने कहा कि आने वाले एक साल में पेट्रोल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी इस बात की चिंता देखी गई। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और विश्वास क्विनिपियाक और फॉक्स न्यूज के अनुसार लगभग आधे मतदाता मानते हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई से अमेरिका कम सुरक्षित हो सकता है, जबकि लगभग 30% का मानना है कि इससे देश सुरक्षित हुआ। ष्टहह के सर्वे में करीब 60% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा कम या बिल्कुल नहीं होने की बात कही। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनओआरसी सर्वे में भी 56% अमेरिकी विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप के फैसलों पर भरोसा कम दिखा रहे हैं। जमीनी सैनिक भेजने को लेकर मत क्विनिपियाक के सर्वे में तीन-चौथाई मतदाता ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने के खिलाफ हैं। केवल 20% लोग इस कदम के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी 52% सैनिक भेजने के खिलाफ हैं, जबकि 37% इसका समर्थन करते हैं। हाल ही में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर ने सार्वजनिक चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि सरकार पहले से यह तय नहीं बता सकती कि यह संघर्ष कितनी दूर तक जाएगा।

ईरान का फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमला: एक भारतीय की मौत

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसी। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। ईरान ने बुधवार रात फारस की खाड़ी में 'सेफसी विष्णु' नाम के एक अमेरिकी तेल टैंकर (जहाज) पर हमला किया। इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी क्क्षह्व के मुताबिक हमले में आत्मघाती नाव (सुसाइड बोट) का इस्तेमाल किया गया। जहाज पर मौजूद बाकी 27 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। ये जहाज मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चल रहा था। फिलहाल मारे गए भारतीय नागरिक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए तीन शर्तें जरूरी हैं 1. ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, 2. युद्ध के नुकसान की भरपाई की जाए, 3. भविष्य में हमला न होने की अंतरराष्ट्रीय गारंटी मिले।

अमेरिकी नाव पर ईरान का हमला, एक भारतीय की मौत : ईरान की तरफ से किए गए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। यह हमला इराक के समुद्री इलाके में एक तेल टैंकर पर हुआ।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सेफसी विष्णु नाम के तेल टैंकर पर हमला किया गया। यह जहाज अमेरिका की कंपनी का है और मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा था। हमला खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में आत्मघाती नाव (सुसाइड बोट) का इस्तेमाल किया गया। जहाज पर मौजूद बाकी 27 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। उन्हें बाद में बसरा शहर ले जाया गया। फिलहाल मारे गए भारतीय नागरिक का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।

ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, फिर कैसे जंग लड़ रहा : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच 12 दिनों से जंग जारी है। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब तक करीब 50 टॉप अधिकारी हमले में मारे गए हैं। इसके बावजूद ईरान दावा कर रहा है कि वह लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। अल जजीरा के मुताबिक इसके लिए ईरान ने एक खास स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें सेना का कमान किसी के पास नहीं बल्कि 7 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दी गई है। इसके अलावा हर पद के लिए 4 संभावित उत्तराधिकारी पहले से तय कर दिए गए हैं।

होर्मुज से भारतीय तेल टैंकरों के लिए रास्ता खोला : सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरानी समकक्ष अब्दुल्ला अब्बास अराघची के बीच हुई बातचीत के बाद ईरान ने होर्मुज जलसंधि से दो भारतीय तेल टैंकरों (पुष्पक और परिमल) के गुजरने की अनुमति दी है।

कुवैत में ड्रोन हमले में दो घायल : कुवैत की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आज सुबह दक्षिणी इलाके में एक दुश्मन ड्रोन ने आवासीय भवन को निशाना बनाया। मंत्रालय के एक्स पोस्ट के अनुसार, इस हमले में कम से कम दो लोग घायल हुए और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा हमले से भवन और संपत्ति को भी सामग्रीगत नुकसान हुआ है।

ईरान के राष्ट्रपति ने दिया शांति और युद्ध समाप्ति पर दिया बयान : ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उन्होंने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत में क्षेत्र में शांति बनाए रखने की ईरान की प्रतिबद्धता दोबारा जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देना, हानियों के लिए मुआवजा देना और भविष्य में किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी प्राप्त करना है। उनके अनुसार यह युद्ध जायनिस्ट शासन और अमेरिका की शुरूआत का परिणाम है और तभी इसे रोका जा सकता है जब इन शर्तों को स्वीकार किया जाए। यूनाइटेड किंगडम की मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने बताया कि यूएई के जेबल अली से लगभग 35 समुद्री मील उत्तर में एक कंटेनर जहाज पर हमला हुआ। एजेंसी के अनुसार जहाज के कप्तान ने रिपोर्ट दी है कि जहाज को अज्ञात प्रक्षेप्य ने निशाना बनाया, जिससे जहाज पर छोटी आग लगी। अंधेरे के कारण पूरी क्षति का आकलन अभी संभव नहीं है। सभी चालक दल सुरक्षित हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सौद अल-ओतैबी ने बताया कि देश की वायु सुरक्षा बलों ने आज सुबह कई दुश्मन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अल-ओतैबी ने कहा कि ये ड्रोन आज सुबह के समय कुवैत के उत्तरी क्षेत्र में देश की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी ड्रोन को समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया और किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है।

नॉर्थ कोरिया में क्रूज मिसाइल टेस्ट, किम जोंग उन ने बेटी के साथ देखी फायरिंग

प्योंगयांग, एजेंसी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ नेवी का स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल टेस्ट देखा। सरकारी मीडिया ने बताया कि यह मिसाइलें चो ह्योन नाम के वॉरशिप से दागी गईं। मिसाइल परीक्षण उस समय हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया जॉइंट सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा जारी तस्वीरों में किम जोंग उन और उनकी बेटी एक कॉन्फ्रेंस रूम में स्क्रीन पर मिसाइल फायरिंग देखते दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों ने देश के पश्चिमी तट के पास टारगेट आइलैंड पर हमला किया। किम जोंग उन ने कहा कि ये टेस्ट नौसेना की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिखाने और सैनिकों को हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए किए गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग की बेटी 'किम जू ऐ', जिनकी उम्र करीब 13 साल बताई जाती है, 2022 के बाद से कई सैन्य परेड और हथियार परीक्षण कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ नजर आ चुकी हैं। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अनुसार, किम जोंग उन उन्हें अपना संभावित उत्तराधिकारी बना सकते हैं। 3 घंटे तक हवा में उड़ती रही मिसाइलें यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं ताकि वह परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल न कर सके. रिपोर्ट

के मुताबिक, नंबर-51 चोए ह्योन नाम के नए डिस्ट्रॉयर से नम्फो तट के पास कई क्रूज मिसाइलें तेजी से दागी गईं. ये मिसाइलें कोरिया के पश्चिमी समुद्र के ऊपर करीब 3 घंटे तक उड़ती रहीं और फिर द्वीपों पर बने टारगेट को निशाना बनाया. स्टेट टीवी के वीडियो में दिखा कि जहाज के पिछले हिस्से में लगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से छह मिसाइलें तेजी से पश्चिम दिशा में दागी गईं. इससे पहले 4 मार्च को हुए परीक्षण में इसी जहाज से पांच मिसाइलें दागी गई थीं. किम ने परीक्षण पर संतोष जताया किम जोंग उन ने परीक्षण की सफलता पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से देश के रणनीतिक हथियारों के कमांड सिस्टम और जहाज की लड़ाकू क्षमता की विश्वसनीयता साबित हुई है. किम ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत अब कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकने वाले नए चरण में पहुंच गई है और उसकी युद्ध रोकने की क्षमता तेजी से मजबूत हो रही है।

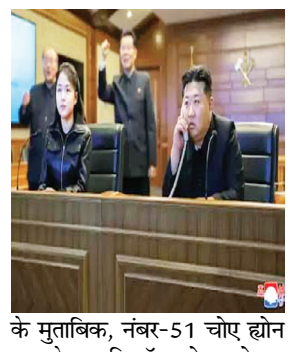

अफगानिस्तान सीमा के पास मोर्टार शेल फटने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

काबुल , एजेंसी। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर जिले की तिराह घाटी में एक मोर्टार का गोला रिहायशी इलाके में आकर गिरा। इस धमाके में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नियाज बादशाह, उनके दो बेटों, एक भतीजे और एक पोते के रूप में हुई है। यह मोर्टार किस दिशा से दागा गया था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की तुरंत जांच करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तानी सेना अफगान तालिबान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चला रही है। पाकिस्तान ने बुधवार को बताया कि पिछले दो हफ्तों से जारी इस कार्रवाई में अब तक 641 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 855 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने 26 फरवरी को 'ऑपरेशन गजब लिल-हक' शुरू किया था। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब अफगान पक्ष ने सीमा पर 53 जगहों पर हमले किए थे। अक्टूबर 2025 के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है।

अमेरिका ने पाकिस्तान में बंद किया अपना वाणिज्य दूतावास, हर साल 75 लाख डॉलर की होगी बचत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। यह राजनयिक मिशन अफगानिस्तान सीमा के सबसे करीब था। साल 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के समय और उसके बाद भी यह जगह अमेरिका के लिए ऑपरेशंस और रसद का मुख्य केंद्र रही है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस हफ्ते कांग्रेस को वाणिज्य दूतावास बंद करने की योजना के बारे में बताया। विभाग का कहना है कि इस कदम से हर साल लगभग 75 लाख डॉलर की बचत होगी। अमेरिका का मानना है कि इस फैसले से पाकिस्तान में उसके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। 'द एसोसिएटेड प्रेस' को मिले एक नोटिस से यह जानकारी सामने आई है। यह फैसला पिछले एक साल से विचाराधीन था। ट्रंप प्रशासन ने लगभग सभी सरकारी एजेंसियों के खर्चों और आकार को छोटा करना शुरू किया है। विभाग ने साफ किया है कि इस फैसले का ईरान के साथ चल रहे तनाव से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, ईरान विवाद की वजह से कराची और पेशावर जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिस कारण वाणिज्य दूतावास ने कुछ समय के लिए अपना काम रोक दिया था। पिछले साल अमेरिकी प्रशासन ने विदेश विभाग के बजट में बड़ी कटौती की थी। इस दौरान हजारों राजनयिकों को हटाया गया और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के स्टाफ में भी भारी कमी की गई। पेशावर वाणिज्य दूतावास पहला ऐसा विदेशी मिशन है, जिसे विभाग के पुनर्गठन की वजह से पूरी तरह बंद किया जा रहा है। नोटिस के अनुसार, पेशावर वाणिज्य दूतावास में 18 अमेरिकी राजनयिक और अन्य सरकारी अधिकारी काम करते हैं। इनके साथ ही 89 स्थानीय कर्मचारी भी वहां तैनात हैं। इस मिशन को पूरी तरह बंद करने में करीब 30 लाख डॉलर का खर्च आएगा। इस रकम का आधा हिस्सा यानी 18 लाख डॉलर उन बख्तरबंद ट्रेलरों को दूसरी जगह ले जाने में खर्च होगा, जो वहां ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। बाकी पैसा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों और ऑफिस के फर्नीचर को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर भेजने में इस्तेमाल होगा। अफगानिस्तान सीमा और काबुल के पास होने की वजह से पेशावर वाणिज्य दूतावास बहुत महत्वपूर्ण था। अब अमेरिकी नागरिकों और अन्य लोगों को वाणिज्य दूतावास से जुड़ी सेवाएं इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से मिलेंगी। इस्लामाबाद यहां से करीब 184 किलोमीटर दूर है।

जापान का कानून : अब पति-पत्नी रख सकेंगे अलग-अलग सरनेम

टोक्यो , एजेंसी। जापान एक ऐसा देश है, जहां पति-पत्नी को एक समान सरनेम रखना जरूरी होता है। जापान का यह 'एक सरनेम' वाला कानून 125 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है, जिसे 1898 के सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। इस नियम के अनुसार, शादी करने वाले जोड़ों को कानूनी रूप से एक ही पारिवारिक नाम यानी सरनेम अपनाना अनिवार्य होता है। हालांकि, अब इस कानून में ढील दी गई। कानून यह नहीं कहता कि सिर्फ पत्नी ही अपना नाम बदलेगी। पति-पत्नी दोनों में से कोई भी अपना सरनेम बदलकर एक समान कर सकता है। लेकिन जापान के पारंपरिक समाज में लगभग 95% मामलों में महिलाओं को ही अपना मायके का नाम छोड़कर पति का सरनेम अपनाना पड़ता है।

इस कानून के खिलाफ हाल के वर्षों में जापान में बड़े पैमाने पर विरोध और कानूनी लड़ाइयां शुरू हुई हैं। कामकाजी महिलाओं का तर्क है कि शादी के बाद नाम बदलने से उनके करियर की पहचान, प्रोफेशनल डिग्री और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में भारी उलझन पैदा होती है। बढ़ते विरोध को देखते हुए जापान सरकार ने इस कानून में बदलाव करने का आश्वासन दिया। अब जापानी सरकार 'चयनात्मक उपनाम प्रणाली' पर विचार कर रही है, ताकि जोड़े अपनी मर्जी से यह तय कर सकें कि उन्हें एक ही नाम रखना है या अपनी पुरानी पहचान बरकरार रखनी है।

क्या है वो कानून : जापान में 1898 से एक कानून चला आ रहा है, जिसे 'कुंसेई' सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। इसके मुताबिक, शादी के बाद पति और पत्नी का सरनेम एक ही होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। आप शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त अलग-अलग सरनेम नहीं लिख सकते। अगर आप अलग नाम रखना चाहते हैं, तो आपकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में जापान इकलौता ऐसा विकसित देश बचा है, जहां यह नियम इतना सख्त है।

नागरिकों का 'सातो' सरनेम : हाल ही में एक जापानी प्रोफेसर ने बताया कि चूंकि जापान में लोग एक ही सरनेम अपना रहे हैं, तो धीरे-धीरे बाकी छोटे सरनेम खत्म होते जा रहे हैं। अगर यह कानून नहीं बदला, तो साल 2531 तक जापान के हर एक नागरिक का सरनेम 'सातो' हो जाएगा। यानी पूरा देश एक ही नाम से जाना जाएगा।

अब क्या बदल रहा है : जापान की जनता और वहां की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यह कानून मानवाधिकारों के खिलाफ है। अब वहां Selective Surname System की मांग हो रही है। इसका मतलब है- शादी करो, लेकिन अपनी मर्जी से तय करो कि नाम बदलना है या पुराना ही रखना है।

जापान की सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस पर बहस हुई है। हालांकि, कोर्ट ने अभी इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया है, लेकिन सरकार को इस पर नया कानून बनाने का सुझाव जरूर दिया है। अब वहां की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है- सरकारी कागजों पर भले ही एक नाम हो, लेकिन ऑफिस, पासपोर्ट और बैंक में महिलाएं अपना 'मैडेन नेम' (शादी से पहले का नाम) इस्तेमाल कर सकती हैं।

नेपाल : चुनाव में जीतने वाली पार्टी के अध्यक्ष बोले, 'भारत के साथ मजबूत करेंगे संबंध'

काठमांडू , एजेंसी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने अपनी पार्टी की चुनावी सफलता पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें 'विकास केंद्रित कूटनीति' के माध्यम से भारत-नेपाल संबंधों के मजबूत होने की आशा है. नेपाल में संसदीय चुनावों में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना मंगलवार को पूरी होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने 165 में से 125 सीटें जीत ली हैं जिससे वह बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है. पार्टी ने आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत 49,74,957 वोट हासिल किए. लामिछाने ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी शुभकामनाओं और 'नेपाल की जनता के लोकतांत्रिक जनादेश को मान्यता देने' के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'आरएसपी और हमारी सरकार आपसी सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी जिसमें आरएसपी 'विकास केंद्रित कूटनीति' को प्राथमिकता देगी. आरएसपी नेता ने कहा, 'हम भारत के साथ ऐसी साझेदारी की आशा करते हैं जो संपर्क, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग के जरिए नयी ऊंचाइयों तक पहुंचे और दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करे.' प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लामिछाने और बालेंद्र शाह को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए दोनों देशों की पारस्परिक समृद्धि,

प्रगति और कल्याण के लिए उनके साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई. शाह नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी होंगे. मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के संबंध आने वाले वर्षों में नए आयाम छुएंगे.' नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीट हैं. इनमें से 165 सदस्य 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (एफपीटीपी) या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं, जबकि 110 सदस्य आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत निर्वाचित होते हैं. निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत सभी 165 सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है और आरएसपी 125 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. अन्य दलों में नेपाली कांग्रेस (एनसी) को 18 सीट मिली हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल को नौ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) को आठ, श्रम संस्कृति पार्टी (एसएसपी) को तीन और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) को एक सीट मिली है। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्वाचित हुआ है।

चीन में नए कानून पर मंथन: एक राष्ट्र-एक पहचान की तैयारी में ड्रैगन?

बीजिंग, एजेंसी। चीन सरकार एक व्यापक 'जातीय एकता' कानून लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर आलोचकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को और कमजोर कर सकता है और उन्हें मुख्यधारा में जबरन समाहित करने की नीति को मजबूत करेगा। कानून का उद्देश्य और प्रावधान यह कानून देश की संसद द्वारा गुरुवार को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके तहत सभी जातीय समूहों के बीच 'समुदाय की मजबूत भावना' को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधि लू किनजियान ने कहा कि यह कानून 'चीनी राष्ट्र' के भीतर सभी जातीय समूहों के बीच एकता को बढ़ावा देगा।

प्रस्तावित कानून के अनुसार, सभी सरकारी निकायों और निजी उद्यमों को जातीय एकता को बढ़ावा देना होगा। इसमें स्थानीय सरकारें और अखिल-चीन महिला महासंघ जैसे राज्य-संबद्ध समूह भी शामिल हैं। कानून में कहा गया है कि देश के प्रत्येक जातीय समूह के लोग, सभी संगठन, सशस्त्र बल, हर पार्टी, सामाजिक संगठन और हर कंपनी को कानून और संविधान के अनुसार 'चीनी राष्ट्र' की एक साझा चेतना बनानी होगी और इस चेतना के निर्माण की जिम्मेदारी लेनी होगी।

पहचान और भाषा पर प्रभाव : अकादमिकों और पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह नया प्रावधान जातीय अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए एक झटका है, क्योंकि यह अनिवार्य शिक्षा में मंदारिन चीनी के उपयोग को अनिवार्य बनाता है। चीन की अधिकांश आबादी हान चीनी है और आधिकारिक भाषा मंदारिन है। देश में 55 जातीय समूह हैं, जो कुल आबादी का 8.9 प्रतिशत हैं। संविधान के अनुसार, 'प्रत्येक जातीय समूह को अपनी भाषा का उपयोग करने और उसे विकसित करने का अधिकार

है' और 'स्व-शासन का अधिकार है'। क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता कानून इन समूहों को सीमित स्वायत्तता का वादा करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए लचीले उपाय शामिल हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि व्यवहार में नया कानून इन प्रावधानों पर हावी होगा। ऑस्ट्रेलिया के ला ट्रोब विश्वविद्यालय में चीन की जातीय अल्पसंख्यक नीतियों पर अध्ययन करने वाले प्रोफेसर जेम्स लिबोल्ड ने कहा कि यह कानून पार्टी के 'सार्थक स्वायत्तता' के मूल वादे को समाप्त कर देगा। उन्होंने इस उपाय को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जातीय नीतियों में 'बड़े पुनर्मूल्यांकन' का एक प्रमुख हिस्सा बताया।

देशी भाषाओं के शिक्षण में स्वायत्तता का अंत : नए कानून के अनुच्छेद 15 के अनुसार, किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक की सभी अनिवार्य शिक्षा में मंदारिन चीनी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। इनर मंगोलिया, तिब्बत और शिनजियांग जैसे चीनी क्षेत्रों में, जहां जातीय अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है, मंदारिन पहले से ही शिक्षा का प्राथमिक माध्यम है। लेकिन नया कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि देश भर में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षा का प्राथमिक माध्यम नहीं हो सकतीं। हाल के वर्षों तक, जातीय अल्पसंख्यकों को स्कूलों में शिक्षण के लिए अपनी भाषाओं का उपयोग करने में कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए, मंगोलिया की सीमा से लगे एक स्वायत्त क्षेत्र इनर मंगोलिया में, छात्र पाठ्यक्रम के बड़े हिस्से को मंगोलियाई में पढ़ सकते थे। यह स्थिति 2020 में बदल गई, जब नए छात्रों को पता चला कि उनके मंगोलियाई भाषा के पाठ्यपुस्तकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल चीनी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना होगा। इस नीतिगत बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और तत्काल कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुनर्शिक्षा अभियान भी चलाए गए। वर्तमान में, इस क्षेत्र के छात्र स्कूलों में प्रतिदिन केवल एक घंटे के लिए मंगोलियाई को एक विदेशी भाषा कक्षा के रूप में पढ़ सकते हैं। यह कानून चीनी सरकार को ऐसे व्यक्तियों या संगठनों पर मुकदमा चलाने के लिए एक कानूनी आधार भी प्रदान करता है जो विदेश में 'जातीय एकता' की प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इजराइल में हैं यूपी के 6004 श्रमिक, सभी के सुरक्षित होने का दावा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इजराइल में कार्यरत राज्य के निर्माण श्रमिकों की कुशलक्षेम पर लगातार नजर रखी जा रही है और वर्तमान में किसी प्रकार की चिंता की स्थिति नहीं है। प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमके शनुगा सुन्दरम् ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुल 6004 निर्माण श्रमिक इजराइल में विभिन्न निर्माण कंपनियों में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों का चयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और इजराइल की सरकारी संस्था पीबा (पापुलेशन, इमीग्रेशन एंड बार्डर अथारिटी) के माध्यम से किया गया था और वर्ष 2024 के दौरान उन्हें इजराइल भेजा गया था। उन्होंने बताया कि ये सभी श्रमिक इजराइल की अलग-अलग निर्माण परियोजनाओं में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार उनके कुशलक्षेम पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय दूतावास से निरंतर संपर्क रखा जा रहा है। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने भी राज्य सरकार को अवगत कराया है कि स्थिति नियंत्रण में है और दूतावास लगातार श्रमिकों के संपर्क में है। फिलहाल किसी श्रमिक ने भारत लौटने को लेकर चिंता व्यक्त नहीं की है। दूतावास ने आपात स्थिति के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन और ईमेल सुविधा भी जारी की है, जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट, इलाके में हड़कंप

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू के आर.एस. पुरा सेक्टर में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को एक संदिग्ध खेप बरामद हुई है। गुरुवार को देर रात लगभग 11:00 बजे, आर.एस. पुरा सेक्टर में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ द्वारा एक संदिग्ध पैकेट बरामद की गई है। माना जा रहा है कि खेप को एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह खेप सीमावर्ती इलाके में एक लिपटे हुए पैकेट के रूप में मिली, इसका वजन करीब 1500 ग्राम था। सूचना मिलते ही, बीएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और इलाके को सुरक्षित किया। बरामद किए गए पैकेट को अभी तक खोला नहीं गया है। बताया जा रहा हैं कि पैकेट को केवल मेटल डिटेक्टर से उचित जांच के बाद ही खोला जाएगा, ताकि इसके अंदर किसी भी विस्फोटक सामग्री की संभावना को पूरी तरह से खत्म हो सके। बरामद की गई खेप की आगे की जांच और तकनीकी परीक्षण जारी है। गौरतलब है कि बदादुरपुर गांव के बाहरी इलाके में खेतों से एक जॉइंट ऑपरेशन में 12 करोड़ कीमत के हाई ग्रेड नारकोटिक्स (संदिग्ध ड्रोन ड्रॉपिंग) की भारी मात्रा बरामद की गई। यह इलाका भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से बस कुछ किलोमीटर दूर है।

13 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए नए पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट ला रहा व्हाट्सएप

नई दिल्ली (एजेंसी)। व्हाट्सएप ने बड़ा ऐलान किया है कि 13 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए नए पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट नाम की शुरुआत कर रहा है। यह सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग तक सिमट कर रह जाएंगे। पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट की मदद से माता-पिता अपने बच्चों की कम्युनिकेशन गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते है। कंपनी ने बताया है कि आने वाले दिनों में इस रोलआउट करेगी। हालांकि किसी टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया है। नए पेरेंट कंट्रोल के तहत माता-पिता ये तय कर सकते हैं कि उनका बच्चा किन लोगों से बातचीत कर सकता है और किन लोगों से नहीं। व्हाट्सएप के पेरेंट्स मैनेज्ड अकाउंट के तहत छोटे बच्चों को मेटा एआई, जैसे फीचर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा। साथ ही कंपनी इन अकाउंट्स से मिलने वाले डेटा का यूज विज्ञापन के लिए नहीं करेगी। पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट को सक्रिय करने के लिए माता-पिता को अपने और अपने बच्चे का डिवाइस एक साथ रखना होगा। इसके बाद क्रिक रिस्पोंस कोड के जरिए दोनों हैंडसेट को लिंक करना होगा। पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट के तहत यूजर्स को सख्त डिफॉल्ट सेटिंग्स, पेरेंट कंट्रोल को और बेहतर किया गया है। कंपनी ने बताया है कि 13 साल से कम उम्र वाले यूजर्स के लिए ये अकाउंट खासतौर से बनाए गए हैं। पैरेंट्स अनजान लोगों से आने वाले मैसेज रिक्वेस्ट का भी रिव्यू कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने बताया है कि इन सेटिंग्स को सिर्फ पेरेंट्स ही बदल सकते हैं। जिसके लिए पहले पिन नंबर से वेरिफाई करना होगा।

आगरा में युवती ने वीडियो वायरल कर दी जान, आरोपी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार

आगरा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के आगरा से खाकी को शर्मसार करने वाला एक बेहद दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पहले युवती ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने अपनी आपबीती बताते हुए एक पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पीड़िता आगरा के ताजगंज थाने में ही तैनात कांस्टेबल जेबी गौतम के साथ पिछले काफी समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवती का आरोप था कि सिपाही ने उसे शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत भरोसे के साथ हुई थी, लेकिन वक्त के साथ यह भरोसा उत्पीड़न और धोखे में बदल गया। युवती ने अपने अंतिम वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा कि कांस्टेबल ने उसे चार साल तक पत्नी की तरह साथ रखा, लेकिन जब शादी की बात आई, तो उसने अपने परिवार का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवती का दर्द साफ छलक रहा था। उसने रोते हुए कहा, जेबी गौतम ने मुझे चार साल बीवी बनाकर रखा और अब छोड़ दिया। जब भी शादी के लिए कहती हूं, तो वह कहता है कि परिवार नहीं मानेगा। युवती ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि क्या वह पुलिसवाला है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? उसने वीडियो में आरोपी कांस्टेबल और उसके परिवार को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मांग की कि उसे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद जरूर मिलना चाहिए।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। परिजनों की तहरीर और वायरल वीडियो को आधार मानकर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया।

दो दशक पुराने वामपंथ को हराकर सीएम बनी ममता... क्या 2026 में दोहरा पाएंगी 2021 की सफलता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य 2016 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2021 और 2026 के चुनावों की तैयारी तक काफी बदल चुका है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रभुत्व वाली 294 सीटों वाली विधानसभा में वाम-कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़ती लोकप्रियता और टीएमसी के सुदृढ़ीकरण के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता, जनसांख्यिकी और मतदाता सूची में बदलाव से प्रभावित हैं।

2016 में टीएमसी ने 2011 की वाम-विरोधी लहर को और मजबूत कर 211 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को केवल 32 सीटें मिलीं (गठबंधन के हिसाब से सीपीएम को 26 और कांग्रेस को 0), जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और घाटाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ सीटें शामिल थीं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें मिलीं, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग और शहरी बाहरी इलाकों में थीं, जो राज्य में भगवा पार्टी की शुरुआती उपस्थिति का संकेत देती हैं। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल (उदाहरण के लिए दक्षिण 24 परगना में 31/31) और शहरी कोलकाता (11 में से अधिकांश सीटें) में शानदार जीत हासिल की, जबकि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों और ग्रामीण हुगली में वामपंथियों की ताकत बनी रही। 2011 के परिसीमन के बाद 23 जिलों में 294 निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर किया गया, जिससे टीएमसी के ग्रामीण आधार को मजबूती मिली।

इसके बाद 2021 के चुनावों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, इसमें भाजपा ने हिंदुत्व-एनआरसी के मंच पर 77 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त हासिल की। बीजेपी ने जंगलमहल (पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा-30 सीटें) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी) में भी बढ़त बनाई। संदेशखाली जैसे मुद्दों और कोविड प्रबंधन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने वापसी कर 213 सीटें जीतीं। टीएमसी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (मालदा, मुर्शिदाबाद, दो 24 परगना- बड़ी बढ़त) में दबदबा बनाए रखा और दक्षिण 24 परगना (31 सीटें), हावड़ा (16) और हुगली (18) में अपनी सीटें बरकरार रखीं। भाजपा ने सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जहां टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं ने 30 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर दिलाए।

अब मार्च 2026 तक, अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के बाद मतदाता सूचियों से 63.66 लाख नाम (मतदाताओं के 10 प्रतिशत से अधिक) हटा दिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों, मतुआ (नमशूद्र) क्षेत्र और अल्पसंख्यक जिलों की 125 से अधिक सीटों पर जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके प्रभावों में मतुआ और उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों में बीजेपी की संभावित बढ़त शामिल है, जहां नाम हटाए गए हैं, और यह टीएमसी के अल्पसंख्यक गढ़ों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को चुनौती दे सकता है, जहां नाम हटाए जाने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना (कुल 64 सीटें), पुरबा बर्धमान (16) और पुरबा मेदिनीपुर (16) जैसे जिलों में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जहां राजकोषीय तनाव (अनुमानित 62,000 करोड़ रुपये का घाटा) विपक्षी चर्चाओं को बल दे रहा है।

भाजपा ने सीमावर्ती और जंगलमहल क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (सीएए-एनआरसी) के भय का फायदा उठाते हुए अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 कर लीं, जबकि टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक (30-40 प्रतिशत वोट बैंक) को एकजुट करके इसका मुकाबला किया। 2011 के बाद परिसीमन ने सीमाएँ तय कर दीं, लेकिन 2026 के एसआईआर मतदाता सूची ने नरम पुनर्निर्धारण का काम किया, जिससे मतुआ (नागरिकता के बाद) में भाजपा को मजबूती मिली और टीएमसी के कल्याणकारी प्रभुत्व की

परीक्षा हुई। आर्थिक संकट - बढ़ता घाटा (2022-23 में 49,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,05,000 करोड़ रुपये का ऋण) - और अंतरिम बजट में किए गए तुष्टीकरण (उत्तरी बंगाल के विकास के बजाय मदरसा निधि का उपयोग) ने विभाजन को और गहरा कर दिया। उत्तर-दक्षिणी बंगाल का विभाजन और गहरा गया है, टीएमसी 200 से अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा गठबंधन के माध्यम से 100 से अधिक सीटों का लक्ष्य बना रही है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन से लेकर टीएमसी-भाजपा के द्विध्रुवीय चुनावी मुकाबले तक के परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें 2026 के चुनाव सीमित सीटों और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी पर निर्भर करेगा।

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, विधानसभा अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजधानी पटना में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें विधानमंडल भवन को विस्फोट से उड़ाने की बात कही गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गए और पूरे विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। बैठक में सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और विधानसभा परिसर की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत रखा जाए। निर्देश मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने विधानमंडल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। प्रवेश द्वारों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और आने-जाने वाले लोगों की कड़ी जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। फिलहाल जांच एजेंसियां उस ईमेल की पड़ताल कर रही हैं जिसके माध्यम से धमकी दी गई थी। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मेल किस स्थान से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

सोनिया गांधी से जुड़े मामले में सुनवाई टली... अब मामले की 30 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित जालसाजी को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन मामले में दायर रिवीजन पिटीशन पर शुक्रवार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली ये सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

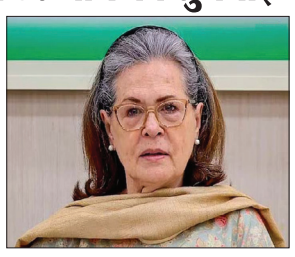

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। इसके बाद अदालत ने नई तारीख दी। ये याचिका वकील विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सितंबर में खारिज किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी फैसले को त्रिपाठी ने चुनौती दी है।

दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका में नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। आरोप है कि नागरिकता मिलने से 3 साल पहले, यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में शामिल था।

इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब सोनिया गांधी के पास 1983 तक नागरिकता नहीं थी, तब 1980 में किस आधार पर और किन दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया? याचिका में ये भी पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से क्यों हटाया गया था?

पिछली सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। उनके वकीलों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। सोनिया गांधी ने याचिका को पूरी तरह से तथ्यहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। इसके पहले इसी मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ जांच और मुकदमा दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल सितंबर में खारिज किया था। कोर्ट ने तब याचिका में पर्याप्त आधार नहीं पाए थे। अब रिवीजन पिटीशन के जरिए ऊपरी अदालत में मामले को फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है।

झारखंड विधानसभा में खुद रिक्शा चलाकर पहुंचे मंत्री इरफान... गैस संकट पर केंद्र सरकार को घेरा

रांची (एजेंसी)। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडर की कथित किल्लत और बढ़ती महंगाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर और अंदर सत्तापक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर के प्रतिरूप (रिप्लिका) और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पोस्टरों पर ÷संसद से नरेंद्र मोदी गायब, देश से सिलेंडर गायब÷ जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों के कारण जनता को गैस की किल्लत और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा दृश्य तब दिखाई दिया, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे। रिक्शे की पिछली सीट पर कृषि मंत्री

शिल्पी नेहा तिर्की बैठी थीं और उनके हाथ में महंगाई के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर थे। इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए उन्होंने बढ़ती कीमतों और गैस संकट के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। विधायक तिर्की ने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके बाद मध्य पूर्व एशिया में पैदा हुई अस्थिरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। उन्होंने इस बात को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति की विफलता बताकर कहा कि इसका सीधा असर देश में महंगाई और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अंसारी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर कहा कि जब राज्य के मंत्री ही पेट्रोलियम संकट और गैस की कमी से जूझ रहे हैं, तब आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सत्तापक्ष के आरोपों को खारिज कर कहा कि गैस की किल्लत का मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है। जेडीयू नेता सरयू राय ने भी दावा किया कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल रहे हैं। सदन में लगातार हंगामे और नारेबाजी के बाद स्पीकर के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई, लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत और महंगाई का मुद्दा पूरे दिन विधानसभा में छाया रहा।

अलविदा की नमाज के बाद लखनऊ में प्रदर्शन, अमेरिका-इजराइल के खिलाफ लगे नारे

लखनऊ(एजेंसी)। रमजान के आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज के बाद शुक्रवार को लखनऊ में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और जमकर नारेबाजी हुई। शहर के कई इलाकों में मस्जिदों के बाहर जमीन पर अमेरिका और इजराइल के झंडे लगाए गए, जिन पर नमाजी आते-जाते समय पैर रखकर गुजरते दिखाई दिए। दरअसल, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। जिसको देखते हुए प्रशासन ने पुराने लखनऊ सहित संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुराने शहर में रूट डायवर्जन भी लागू किया गया। उधर, ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद की इमामत में अलविदा की नमाज अदा की गई। वहीं टीले वाली मस्जिद में भी बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज पढ़ी। इसके अलावा बड़ा इमामबाड़ा परिसर स्थित आसिफी मस्जिद में शिया समुदाय के लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की। नमाज के बाद कुछ स्थानों पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी हुए।

राहुल गांधी की देश को गुमराह करने और भारत की छवि खराब करने की आदत बन गई

-केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के नेता पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने और वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। संसद के बाहर गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यह आदत बन गई है कि वे देश में भ्रम फैलाते हैं और विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। मकर द्वार पर चाय पीते हुए और देश का अपमान करते हुए उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी देश में भ्रम फैलाया।

गिरिराज की ये टिप्पणियां केंद्र और विपक्ष के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच आई हैं, जिसे पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति पर इसके प्रभाव ने और हवा दी है। एक दिन पहले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कहा था कि दर्द तो अभी शुरू हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के

वैश्विक और घरेलू स्तर पर दूरगामी परिणाम होने की संभावना है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि इसका असर देश भर में महसूस होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि रेस्तरां और होटल बंद हो रहे हैं और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों में दहशत है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग जारी है। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे वैश्विक तेल का 20फीसदी प्रवाह होता है, बंद कर दिया गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, खासकर हमारे लिए क्योंकि हमारे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज से ही होकर गुजरता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की स्थिरता की नींव होती है। उन्होंने भारत की ऊर्जा साझेदारी संबंधी निर्णयों को बाहरी शक्तियों के प्रभाव में लेने के विचार की आलोचना की।

हापुड़ में नेता के घर से 55 एलपीजी सिलेंडर बरामद, गैस संकट के बीच जमाखोरी का भंडाफोड़

हापुड़ (एजेंसी)। जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध जमाखोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। एक तरफ जहां आम जनता वैश्विक तनाव और आपूर्ति में बाधा के कारण रसोई गैस के एक-एक सिलेंडर के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों को छिपाकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हापुड़ प्रशासन की टीम ने स्थानीय नेता अब्दुल रेहान के आवास पर छापेमारी कर वहां से 55 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब पूरे क्षेत्र में गैस की भारी किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गैस संकट का फायदा उठाकर सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर रहे हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसी क्रम में जब अधिकारियों को अब्दुल रेहान के घर पर बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा होने की सटीक जानकारी मिली, तो संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम ने वहां छापेमारी की। घर के भीतर और स्टोर रूम में सिलेंडरों का बड़ा जखीरा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। प्रशासन ने तत्काल सभी 55 सिलेंडरों को जब्त कर लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से संबंधित विभाग को सौंप दिया।

इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों के चक्कर काटने और कई दिनों के इंतजार के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि प्रभावशाली लोग अपने घरों में सिलेंडरों का अंबार लगाए बैठे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि इस तरह की जमाखोरी ही बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर रही है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है।

प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गैस एजेंसियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये सिलेंडर किन नामों पर बुक किए गए थे और बिना वितरण के एक ही स्थान पर कैसे पहुंचे। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद, प्रशासन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। हापुड़ देहात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज ने बताया कि आरोपी अब्दुल रेहान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चूंकि मामले में सजा का प्रावधान सात साल से कम है, इसलिए आरोपी को फिलहाल थाने से जमानत दे दी गई है, लेकिन जांच जारी है और जल्द ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

भारत में अलग है इच्छामृत्यु का तरीका, कई देशों में जहरीला इंजेक्शन व आत्महत्या भी है प्रावधान

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में इच्छामृत्यु को लेकर कानूनी और मानवीय बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने गाजियाबाद के 32 साल के हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते हुए उनके कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरण हटाने की मंजूरी दे दी। हरीश पिछले 13 सालों से कोमा में है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली स्थित एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया मानवीय और सम्मानजनक तरीके से की जानी चाहिए और मरीज को पैलिएटिव केयर में रखा जाए ताकि उसे कम से कम कष्ट हो। निष्क्रिय इच्छामृत्यु वह प्रक्रिया है जिसमें मरीज को जीवित रखने वाले कृत्रिम साधनों या इलाज को रोक दिया जाता है। इसमें वेंटिलेटर, कृत्रिम पोषण, फीडिंग ट्यूब या अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण हटा दिए जाते हैं। इसके बाद मरीज की मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि इलाज जारी रखने से केवल शरीर को कृत्रिम रूप से जिंदा रखा जा रहा होता है और स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं रहती। भारत में इस प्रक्रिया को 'गरिमापूर्ण मृत्यु' के अधिकार से जोड़कर देखा जाता है।

बता दें भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। हालांकि यहां सक्रिय इच्छामृत्यु यानी किसी मरीज को जानबूझकर घातक इंजेक्शन या दवा देकर मृत्यु देने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर दुनिया के कई देशों में इच्छामृत्यु के अलग-अलग रूपों को कानूनी मान्यता मिली है। अमेरिका के कुछ राज्यों में डॉक्टर की सहायता से आत्महत्या की अनुमति है, जबकि नीदरलैंड में डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन देकर या चिकित्सा सहायता से इच्छामृत्यु दोनों मान्य हैं। कनाडा में भी चिकित्सकीय सहायता से इच्छामृत्यु को कानूनी स्वीकृति दी गई है।